Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 02
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शुक्रवार, 09 जनवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 'ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो दृश्य ...
4 शिक्षा का स्वदेशीकरण : विकसित भारत...
7 एसए20 शानदार मंच पर आईपीएल से ..

संक्षिप्त न्यूज

थलपति विजय की फिल्म पर 'सेंसर ब्लॉक'? कांग्रेस का आरोप- सत्ता का दुरुपयोग कर रही मोदी सरकार

चेन्नई **(एजेंसी)**। तमिलनाडु कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडंकर ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया, क्योंकि तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय की फिल्म 'जना नायकन' को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में देरी हो रही है। चोडंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, 'प्रिय प्रधानमंत्री कार्यालय और नरेंद्र मोदी, अभिनेता विजय की फिल्म 'जना नायकन' से जुड़े विवाद ने राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। राजनीतिक मतभेद समझ में आते हैं, लेकिन किसी कलाकार के काम को निशाना बनाना अस्वीकार्य है।'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि तमिलनाडु की जनता राजनीतिक लाभ के लिए सिनेमा पर सेंसरशिप बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कला और मनोरंजन को राजनीतिक लड़ाइयों में मोहरे के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। चोडंकर ने कहा कि तमिलनाडु की जनता राजनीतिक लाभ के लिए सिनेमाघरों पर सेंसरशिप बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि कला और मनोरंजन को राजनीतिक लड़ाइयों में मोहरे के रूप में इस्तेमाल न होने दें। विजय की फिल्म आपके दबाव के कारण देरी का सामना कर रही है, जो निर्माताओं और प्रशंसकों के लिए अनुचित है। आइए कला से राजनीति को दूर रखें और रचनात्मक स्वतंत्रता का सम्मान करें।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अभिनेता विजय से नहीं, बल्कि राजनेता विजय से मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी, अभिनेता विजय से नहीं, बल्कि राजनेता विजय से मुकाबला करके अपने 56 इंच के सीने के दावे को साबित करें। याद रखें, आपकी धमकी भरी राजनीति तमिलनाडु में काम नहीं करेगी।

विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के उद्घाटन में भाग लेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 10 जनवरी को खेल और युवा कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे जबकि समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे।

दस विभिन्न थीम पर भारत मंडपम में होने वाले तीन दिवसीय संवाद में देश भर के दो हजार से अधिक युवा भाग लेंगे जबकि विदेश मंत्रालय के 'भारत को जाने' कार्यक्रम से 80 भारतवंशी युवाओं का चयन भी इसके लिये किया गया है।

समारोह के पहले दिन भारत की विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर, महान बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच पुलेला गोपीचंद, टेनिस धुरंधर लिएंडर पेस भी

प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। मंत्रालय ने बताया , " उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद रहेंगे।"

पहले दिन नौ जनवरी को प्रतिस्पर्धाओं के विभिन्न वर्गों के चयन राउंड होंगे। इसके अलावा प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय और प्रधानमंत्री संग्रहालय घुमाया जायेगा।

इस बार विकसित भारत चैलेंज ट्रैक के लिये दस थीम रखी गई हैं जिनमें लोकतंत्र और सरकार में युवा, महिला नीत विकास :विकसित भारत की कुंजी, फिट भारत, हिट भारत, आत्मनिर्भर भारत : मेक इन इंडिया, मेक फोर वर्ल्ड और विकसित भारत के लिये भविष्योन्मुखी कार्यबल का निर्माण प्रमुख है।

विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद खेल और युवा कार्य मंत्रालय की पहल है जो भारत के युवाओं को विकसित भारत का विजन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाने का प्रयास है। मंत्रालय ने बताया कि प्रतिभागियों का चयन देश भर में विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं के जरिये हुआ जिसमें निबंध लेखन और क्विज शामिल है जिसमें 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया।

बारह जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाग लेंगे। एक अधिकारी ने बताया , " प्रधानमंत्री इस मौके पर युवाओं को संबोधित करेंगे और विकसित भारत 2047 के लिये युवा प्रतिभागियों के सर्वश्रेष्ठ सुझाव उनके समक्ष रखे जायेंगे।

आम आदमी की पार्टी का चुनावी मंत्र! केजरीवाल बोले- जनता जिसे चाहेगी, आप उसे टिकट देगी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि पार्टी उन आम लोगों को चुनावी टिकट देने के लिए प्रतिबद्ध है जो अपने काम के जरिए जनता का विश्वास और समर्थन हासिल करते हैं। लुधियाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग है क्योंकि यह पैसे, प्रभाव या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर टिकट नहीं बांटती है।

केजरीवाल ने एएनआई से कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों को टिकट देने वाली पार्टी है। आपको टिकट केवल आपके काम के आधार पर ही मिल सकता है। केजरीवाल उसी को टिकट देंगे जिसे जनता पसंद करती है। आप के संस्थापक सिद्धांतों को दोहराते हुए केजरीवाल ने कहा कि पार्टी का गठन आम पृष्ठभूमि के ईमानदार और सक्षम व्यक्तियों को राजनीति में लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और जन-केंद्रित शासन के लिए किया गया था।

इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए उसे पंजाब विरोधी और सिख विरोधी बताया। मुख्यमंत्री मान ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी जी के वीडियो में गुरु तेग बहादुर जी के नाम का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा से सार्वजनिक माफी की मांग की, जिसे उन्होंने शर्मनाक कृत्य बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, मान ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आतिशी जी के उन शब्दों को जोड़ा है ।

गुरुओं के अपमान पर सियासत गर्म, भाजपा बोली- आतिशी की सदस्यता रद्द हो, केजरीवाल माफी मांगें

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी द्वारा गुरु तेग बहादुर के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए पार्टी से उनकी सदस्यता रद्द करने और तत्काल माफी मांगने की मांग की। एक आधिकारिक बयान में सूद ने कहा कि आतिशी को सदन से भागने और मामले का राजनीतिकरण करने के बजाय विवाद के लिए माफी मांगनी चाहिए थी।

आशीष सूद ने कहा कि आरोप लगाने के बजाय, आतिशी को सदन में आकर यह स्पष्ट करना चाहिए था कि उन्होंने वास्तव में ऐसा क्या कहा जिससे यह विवाद उत्पन्न हुआ, खासकर तब जब सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही गुरुओं के सम्मान की बात कर रहे थे। हमारे समाज में यह मान्यता है कि यदि कोई गलती हो जाती है और वह माफी मांग लेता है, तो वह व्यक्ति महान बन जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई होती और उन्होंने माफी मांग ली होती, तो पूरा देश उन्हें माफ कर देता। लेकिन इसके बजाय, सदन से भाग जाना, मुद्दे का राजनीतिकरण करना और सदन की संपत्ति के आधिकारिक वीडियो को झूठा बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

सूद ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला करते हुए गुरुओं के कथित अपमान के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की और भाजपा की आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह हठधर्मिता केवल आतिशी तक सीमित नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को दर्शाती है। गुरुओं का अपमान करने के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनकी पूरी टीम को देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कल, हमारे सभी मंत्रियों और विधायक दल की ओर से, हमने आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की।

जस्टिस वर्मा पर लोकसभा से बनेगी कमेटी?

महाभियोग पर एलएस स्पीकर के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें उनके आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के संबंध में उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति गठित करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कल, न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति में कुछ खामियां हैं, और न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या ये खामियां इतनी गंभीर हैं कि कार्यवाही समाप्त करने की आवश्यकता हो। 16 दिसंबर, 2025 को न्यायालय ने रिट

याचिका के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को नोटिस जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पहली नजर में जजेज (इंक्वायरी) ऐक्ट, 1968 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनी समिति पर कोई रोक नहीं है। भले ही इसी तरह का प्रस्ताव राज्यसभा में खारिज कर दिया गया हो। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने की। जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत बनी संसदीय जांच कमिटी की वैधता को चुनौती दी है। यह मामला उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में जला हुआ कैश मिलने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को नोटिस जारी किया था।

राज्यसभा से प्रस्ताव खारिज, क्या लोकसभा बना सकता है कमिटी जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुआई वाली बेंच ने पहली नजर में जस्टिस वर्मा की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी की कुछ दलीलों से असहमति जताई। रोहतगी ने दलील दी कि अगर महाभियोग के प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही दिन पेश किए गए हों, तो जांच कमिटी का गठन दोनों सदनों से संयुक्त रूप से होना चाहिए। चूंकि, राज्यसभा में प्रस्ताव खारिज हो गया, इसलिए लोकसभा को अकेले जांच समिति बनाने का अधिकार नहीं है।

DMK से दरार की खबरों के बीच कांग्रेस का बड़ा दांव, Tamil Nadu चुनाव के लिए उतारी दिग्गजों की टीम

नई दिल्ली। आगामी 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत कांग्रेस ने विशेष पर्यवेक्षकों की एक टीम नियुक्त की है। बुधवार को इस फैसले की घोषणा की गई, जिसमें पार्टी नेताओं ने राज्य भर में संगठनात्मक समन्वय और पहुंच को मजबूत करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की बात कही। तमिलनाडु के लिए कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षकों में मुकुल वासनिक, उत्तम कुमार रेड्डी और मोहम्मद निजामुद्दीन शामिल हैं। इस सूची से पहले ही गिरीश चोडंकर को तमिलनाडु कांग्रेस के राज्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा चुका था।

घोषणा के अनुसार, कांग्रेस ने विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव तैयारियों की निगरानी के लिए पार्टी के अनुभवी सदस्यों को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया है। इन पर्यवेक्षकों को स्थानीय इकाई की गतिविधियों की निगरानी करने, राज्य और ब्लॉक स्तर के नेतृत्व के बीच संचार को सुगम बनाने और पार्टी की चुनाव रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाएगा। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने राज्य में इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह

की दरार की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस और डीएमके मजबूती से एकजुट हैं और अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

तमिलनाडु में गठबंधन की स्थिति पर एएनआई से बात करते हुए, टैगोर ने विपक्षी गठबंधन के लिए राज्य के राजनीतिक महत्व और कांग्रेस-डीएमके संबंधों की गहराई को रेखांकित किया। टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण राज्य है, और हम सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन एक महत्वपूर्ण गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस एक हिस्सा है और डीएमके इसकी प्रमुख सहयोगी है। हमने आठ चुनाव एक साथ लड़े हैं, क्योंकि डीएमके कांग्रेस की दीर्घकालिक सहयोगी है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेदों की खबरों पर बोलते हुए टैगोर ने गठबंधन में बदलाव की किसी भी संभावना से इनकार किया, हालांकि उन्होंने समय पर बातचीत की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने बुधवार को कहा कि मुझे नहीं लगता कि सहयोगी साझेदारों में बदलाव को लेकर कोई चर्चा होगी। कांग्रेस डीएमके की दीर्घकालिक सहयोगी है। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि सीट वार्ता जल्द से जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि किसी भी देरी से गठबंधन की छवि पर असर पड़ सकता है।

टैगोर ने तमिलनाडु में भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर भी निशाना साधा और उस पर क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करके अपना प्रभाव बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा किसी भी तरह से तमिलनाडु में प्रवेश करना चाहती है। वे एआईएडीएमके को खत्म करके उसकी जगह लेना चाहते हैं, क्योंकि वे आपसे दोस्ती करेंगे और धीरे-धीरे आपके वोटों को बटोर लेंगे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ वे यही तरीका अपना रहे हैं।

निकम्मे गृह मंत्री...ईडी ने कहां मारा छापा? अमित शाह पर बुरी तरह भड़क गईं ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता स्थित आई-पैक कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कड़ी निंदा की है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी पार्टी के दस्तावेज ले गई है और भाजपा को चेतावनी दी है कि उनके राज्य कार्यालय पर भी इसी तरह की छापेमारी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा क्या ईडी और अमित शाह का यह कर्तव्य है कि वे पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करें? ये निकम्मे गृह मंत्री, जो देश की रक्षा नहीं कर सकते, मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज ले जा रहे हैं। अगर मैं भाजपा के कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा? एक तरफ वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर (सूचना, सूचना और निरीक्षण) करके सभी मतदाताओं के नाम मिटा रहे हैं... चुनावों के कारण वे मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारी जुटा रहे हैं।

ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें

बंगाल के आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया और काजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की खदानों से संबंधित कई करोड़ रुपये के कोयले की चोरी का आरोप लगाया गया था। स्थानीय कोयला व्यापारी अनूप मांझी उर्फ ??लाला इस मामले में मुख्य संदिग्ध है। ईडी ने इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी (38) से पूछताछ की थी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ईडी ने दावा किया कि अवैध कोयला व्यापार से प्राप्त धन के वह लाभार्थी हैं।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आई-पैक की स्थापना की थी। बाद में उन्होंने जन सुराज नामक एक राजनीतिक दल बनाया, जिसे पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनावों में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इस परामर्श फर्म ने 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ काम किया था।

कर्नाटक सरकार ने नए रोजगार कानून वीबी जी-राम-जी को मामने से किया इनकार, हाईकोर्ट में देगी चुनौती

बंगलूरू। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को कहा कि राज्य कैबिनेट ने हाल ही में लागू किए गए वीबी-जी-राम जी अधिनियम को स्वीकार न करने का फैसला किया है। यह कानून यूपीए सरकार के समय शुरू की गई ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा (मनरेगा) की जगह लाया गया है। कैबिनेट ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म किए जाने और उसकी जगह विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू करने के खिलाफ 'जनता की अदालत' में जाने का भी फैसला किया है।

'योजना बनाने की प्रक्रिया को पहुंचेगा नुकसान'

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए पाटिल ने कहा, सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम को स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे कानून की अदालत में चुनौती दी जाएगी। इस मुद्दे पर तैयार कैबिनेट प्रस्ताव में कहा गया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए काम और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह कानून संविधान की ओर से पंचायतों को दिए गए वैध अधिकारों को कमजोर करता है और संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों की भावना के खिलाफ है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीचे से ऊपर की योजना बनाने की प्रक्रिया को इससे नुकसान पहुंचा है।

'राज्यों को परामर्श प्रक्रिया से बाहर रखा गया'

कैबिनेट ने कहा कि यह कानून संघीय ढांचे को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें न केवल राज्यों को परामर्श प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है, बल्कि उनसे कुल खर्च का 40 फीसदी वहन करने की अपेक्षा भी की गई है। यह सब राज्यों को भरोसे में लिए बिना केंद्र सरकार की ओर से एकतरफा तय शर्तों के अनुसार किया गया है।

'ग्रामीण जनता के आर्थिक अधिकारों पर चोट करता है कानून'

कैबिनेट ने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर गंभीर चोट करता है। एक तरफ काम केवल उन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी और दूसरी तरफ मजदूरी दर भी केंद्र तय करेगा, जिसमें राज्य सरकारों की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है।

कैबिनेट के अनुसार, यह कानून महात्मा गांधी की 'ग्राम स्वराज' की कल्पना के भी खिलाफ है। कैबिनेट ने यह भी कहा कि पंचायतों को न तो स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम चुनने की आजादी होगी और न ही कामों की प्राथमिकता तय करने का अधिकार। इसके अलावा, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से तय मानक तक ही सीमित रखा जाएगा।

'मराठी मानुष' के लिए साथ आए Uddhav-Raj Thackeray, बोले- बीजेपी को सत्ता से बाहर करना जरूरी

दिव्यांश
मुंबई(संवाददाता)

एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की चाह रखने वाले लोग केंद्र और राज्य में सत्ता में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वे नगर निगमों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो 'मराठी मानुष' शक्तिहीन हो जाएंगे। राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के संयुक्त साक्षात्कार के पहले भाग में, जो गुरुवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित हुआ, महाराष्ट्र निर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख ने कहा कि वे और उनके चचेरे भाई अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि राज्य में 'मराठी मानुष' के अस्तित्व के लिए एक साथ आए हैं। ठाकरे चचेरे भाइयों का साक्षात्कार शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत और जाने-माने निर्देशक महेश मांजरेकर ने लिया। दोनों भाइयों ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए पिछले महीने गठबंधन की घोषणा की थी। राज ठाकरे ने सामना को दिए साक्षात्कार में कहा कि राज्य के बाहर से लोग न केवल आजीविका के लिए आ रहे हैं बल्कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया, 'यह एक पुराना घाव है। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के सपने को साकार करने के प्रयास जारी हैं।' राज ने कहा कि आज का माहौल कुछ वैसा ही है जैसा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान था, जब गुजरात चाहता था कि मुंबई उसका हिस्सा हो जाए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की चाह रखने वाले केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में हैं।'

मनसे प्रमुख ने दावा किया कि अगर वे (भाजपा) महानगर पालिकाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मराठी मानुष कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मनसे प्रमुख ने कहा कि अगर इस पर लगाम लगानी है, तो खासकर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, मीरा-भयंदर, कल्याण-डोम्बिवली और छत्रपति संभाजीनगर में नगर निकायों पर नियंत्रण जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विकास का ढोंग तो करती है, लेकिन इससे प्रगति की बजाय विनाश होता है।उन्होंने दावा किया कि यह 'बिना योजना के विकास' है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'सरकार को खुद नहीं पता कि वह क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से सत्ता में बैठे लोग मराठी या महाराष्ट्र से हैं लेकिन मुंबई की जनता से उनका कोई लेना-देना नहीं है। शिवसेना (उबाठा) प्रमुख ने आरोप लगाया, 'वे सिर्फ ठेकेदारों के लिए काम करते हैं।

अंबरनाथ में गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस को लगा एक और झटका, सभी निलंबित 12 पार्षद भाजपा में शामिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां उसके 12 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होकर पार्टी की स्थिति को और मजबूत किया है। उम्मीद है कि इस कदम से भगवा पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। ये 12 पार्षद नवी मुंबई स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख रविंद्र चव्हाण की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस ने अब इन पार्षदों को निलंबित करने का फैसला किया है और उनके इस कदम को अवैध और असंवैधानिक बताया है। एक बयान में कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि इन 12 पार्षदों ने भाजपा में शामिल होकर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें नोटिस भी जारी करेगी।

सावंत ने कहा कि यह कृत्य पूरी तरह से गैरकानूनी है। किसी पार्टी के चिन्ह पर निर्वाचित होने के बाद स्वतंत्र समूह बनाना या बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना न केवल अनैतिक है बल्कि असंवैधानिक भी है। कांग्रेस पार्टी इन पार्षदों की सदस्यता रद्द करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। जल्द ही इन सभी को कानूनी नोटिस जारी किए जाएंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 12 पार्षद कौन हैं?

प्रदीप नाना पाटिल
दर्शन उमेश पाटिल
अर्चना चरण पाटिल
हर्षदा पंकज पाटिल
तेजस्विनी मिलिंद पाटिल
विपुल प्रदीप पाटिल
मनीष म्हात्रे
धनलक्ष्मी जयशंकर
संजवनी राहुल देवड़े
दिनेश गायकवाड
किरण बद्रीनाथ राठौड़
कबीर नरेश गायकवाड

अबु आजमी बनाम रईस शेख ने बढ़ाई सपा की मुश्किलें, अखिलेश यादव का दौरा रद्द

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों से पहले, पार्टी के भीतर नए सिरे से अशांति फैल गई है। समाजवादी पार्टी (एसपी) के विधायक रईस शेख महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी के बीच राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। 3 जनवरी की बात है जब रईस शेख ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अबू आज़मी की गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई थी। शेख ने पत्र में आज़मी पर जानबूझकर उन्हें परेशान करने और पार्टी में भारी व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया था। अब खबर आ रही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीएमसी चुनाव प्रचार का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

अखिलेश को बीते दिनों लिखे गए पत्र में पत्र में रईस शेख ने आरोप लगाया है कि अबू आज़मी ने भिवंडी और मुंबई नगर निगम चुनावों में मनमाने ढंग से टिकट वितरण किया है। शेख का दावा है कि आजमी पार्टी कार्यकर्ताओं और संभावित उम्मीदवारों के हितों की अनदेखी करते हुए मनमानी कर रहे हैं। विधायक के अनुसार, इस कुप्रबंधन से 'पार्टी सदस्यों में असंतोष पैदा हो रहा है और इन महत्वपूर्ण चुनावों में पार्टी की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। शेख आगे कहते हैं कि आजमी की सार्वजनिक टिप्पणियों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं।

पार्टी चुनाव नतीजों के बाद दोनों के बीच की इस खींचतान पर फैसला ले सकती है। समाजवादी पार्टी मुंबई की खास सीटों के अलावा भिवंडी और आसपास के कुछ इलाकों में मजबूत मानी जाती है। पिछले चुनाव में सपा के मुंबई में सात नगरसेवक थे। जिनमें से एक भायखला और छह नगरसेवक गोवंडी से जीते थे। सपा के भायखला के प्रभाग से रईस शेख नगरसेवक रह चुके हैं। उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए यहां से टिकट मांगा था। लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने अपने करीबी वकार को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया है।

नवी मुंबई के इस वार्ड में चुनाव पर लगी रोक, भाजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने का आदेश स्थगित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17ए (वाशी) में होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के उस आदेश को भी स्थगित कर दिया, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया था। मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) का हवाला देते हुए बीजेपी नेता नीलेश भोजाने का नामांकन खारिज कर दिया था। इसका आधार उनकी संपत्ति पर अवैध निर्माण बताया गया था।

अदालत ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने भोजाने का नामांकन खारिज करके 'पहली नजर में गैर-कानूनी और मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है'। अपने अंतरिम आदेश में, अदालत ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए भोजाने का नामांकन खारिज करने के फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य चुनाव आयोग, कमिश्नर और चुनाव अधिकारी वार्ड नंबर 17ए की पार्षद सीट के चुनाव को लेकर फिलहाल कोई आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

क्या था मामला?

भोजाने ने रिटर्निंग ऑफिसर के 31 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके नॉमिनेशन को अमान्य ठहराया गया था। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पार्षद बनने के लिए अयोग्य होगा यदि उसने या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य ने कोई अवैध या अनाधिकृत निर्माण किया है। अपनी याचिका में भोजाने ने तर्क दिया कि यह धारा केवल मौजूदा पार्षद पर लागू होती है, उम्मीदवारों पर नहीं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना अलग बात है, लेकिन अधिकारियों का शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना गंभीर विषय है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को राहत देना जरूरी था क्योंकि प्रथम दृष्टया में यह धारा उनके मामले में लागू नहीं होती।

चुनाव ड्यूटी में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होंगे - नवी मुंबई के स्कूल प्रिंसिपलों को आखिरी चेतावनी

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आम चुनाव 2025-26 के सिलसिले में चुनाव के काम के लिए रखे गए कर्मचारियों को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत गंभीरता से लिया है। 15 जनवरी 2026 को होने वाली वोटिंग को देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे के निर्देश पर, 8 जनवरी 2026 को नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर के ज्ञान केंद्र में 101 स्कूलों के हेड की एक अर्जेंट मीटिंग हुई।

इस मीटिंग में चुनाव के काम पर न आने वाले 451 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर डॉ. राहुल गेठे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर श्री किसनराव पलांडे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर श्री संघरत्न खिल्लारे और एजुकेशन ऑफिसर श्री अशोक कडूस ने इस मीटिंग में बताया कि चुनाव का काम एक नेशनल ड्यूटी है और यह काम करना ज़रूरी है। चुनाव विभाग के निर्देशानुसार, संबंधित 101 स्कूलों के जो कर्मचारी अभी तक चुनाव के काम पर नहीं आए हैं, उन्हें आज ही दोपहर 2 बजे तक उनके आदेश में बताए गए रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिया गया है कि जो कर्मचारी शाम 4 बजे तक ड्यूटी पर नहीं आएंगे, उनके नाम तुरंत प्रशासन को बताएं। प्रशासन ने साफ किया है कि संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से मिली गैरहाजिर कर्मचारियों की लिस्ट के अनुसार, इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ चुनाव ड्यूटी में रुकावट डालने के लिए पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जाएगी।

इस मीटिंग के मौके पर गाइडेंस देते हुए शिक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर संघरत्न खिल्लारे ने बताया कि सरकार के फैसले के अनुसार, लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी के चुनाव का काम सभी तरह के मैनेजमेंट कर्मचारियों के लिए जरूरी है। हर कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह पांच साल में एक बार दो दिन की ट्रेनिंग और दो दिन असली चुनाव देकर लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा ले। 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए यह काम बहुत ज़रूरी है, और सभी गैरहाज़िर कर्मचारियों से कहा गया है कि वे किसी भी सख्त कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी जगह पर रिपोर्ट करें।

मध्य रेल ने अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा करने वाले 30.75 लाख यात्रियों से 183.16 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया

मध्य रेल अपने सम्मानित यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के तहत, अपने पूरे नेटवर्क में अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रहा है।

टिकट जांच के गहन और व्यवस्थित अभियानों के माध्यम से, मध्य रेल ने वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर 2025) के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 मध्य रेल की समर्पित टिकट जाँच टीमों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर 2025) के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे, गलत या अमान्य यात्रा प्राधिकरण वाले 30.75 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 28.01 लाख यात्रियों को पकड़ा गया था, जो लगभग 10% की वृद्धि है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर 2025) के दौरान जुर्माने के रूप में रिकॉर्ड 183.16 करोड़ रुपये वसूले गए, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 151.99 करोड़ रुपये वसूले गए थे, जो 20% से अधिक की वृद्धि है।

दिसंबर 2025 के दौरान

मध्य रेल की टिकट जाँच टीमों ने बिना टिकट यात्रा करने वाले, गलत या अमान्य यात्रा प्राधिकरण वाले 3.24 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि दिसंबर 2024 में यह संख्या 2.93 लाख थी, जो 10% से अधिक की वृद्धि दर्शाती है।

दिसंबर 2025 में अपराधियों से जुर्माने के रूप में 18.25 करोड़ रुपये वसूले गए, जबकि दिसंबर 2024 में यह राशि 13.55 करोड़ रुपये थी, जो लगभग 35इ की वृद्धि दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर 2025) के लिए बिना टिकट/वैध टिकट के यात्रा करते पकड़े गए यात्रियों का मंडलवार विवरण और उनसे वसूल की गई जुर्माने की राशि इस प्रकार हैः

भुसावल मंडलः 7.54 लाख मामलों से 63.83 करोड़ रुपये,
मुंबई मंडलः 12.82 लाख मामलों से 55.12 करोड़ रुपये,
पुणे मंडलः 3.41 लाख मामलों से 20.84 करोड़ रुपये
नागपुर मंडलः 3.33 लाख मामलों से 20.75 करोड़ रुपये,
सोलापुर मंडलः 1.81 लाख मामलों से 8.39 करोड़ रुपये और
मुख्यालयः 1.83 लाख मामलों से 14.22 करोड़ रुपये

मध्य रेल अनधिकृत यात्रा का पता लगाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाता है, जिसमें स्टेशन चेक, एम्बुश चेक, फोर्ट्रेस चेक, गहन चेक और मेगा टिकट चेकिंग अभियान शामिल हैं। ये परिचालन सभी मंडलों में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, स्पेशल ट्रेनों के साथ-साथ मुंबई और पुणे मंडलो में उपनगरीय ट्रेनों पर भी किया जाता है।

मध्य रेल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे अधिकृत विक्रेताओं द्वारा जारी वैध टिकटों के साथ, रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटरों से, एटीवीएम के माध्यम से या वेबसाइट http://www.irctc.co.in के माध्यम से टिकट बुक करें। यात्री अपने मोबाइल फोन पर रेल वन ऐप डाउनलोड करके भी टिकट बुक कर सकते हैं।

मध्य रेल यात्रियों से यह भी अनुरोध करता है कि वे फर्जी टिकट बनवाने/प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का सहारा न लें और उन पर यात्रा न करें। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के तहत दंडनीय है, जिसमें जुर्माना और 7 वर्ष तक की कैद या दोनों हो सकते हैं। रेलवे बिना टिकट यात्रा के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराता है और यात्रियों को आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुरक्षित यात्रा करें, जिम्मेदारी से यात्रा करें, गरिमा के साथ यात्रा करें

मतदान का संदेश देने के लिए कोपरखैरणे क्षेत्र में विद्यार्थियों ने बनाई मानव श्रृंखला

नवी मुंबई महानगरपालिका चुनावों में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर आयुक्त एवं चुनाव अधिकारी के मार्गदर्शन में 'स्वीप' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में नवी मुंबई महानगरपालिका के विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों ने एकत्र होकर कोपरखैरणे क्षेत्र में विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया और महानगरपालिका चुनाव में मतदान करने की अपील की।

यह अभिनव पहल चुनाव संबंधी स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के उप आयुक्त के मार्गदर्शन में, शिक्षा विस्तार अधिकारी एवं केंद्र समन्वयक के पर्यवेक्षण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

कोपरखैरणे क्षेत्र में निकाली गई इस रैली के दौरान विद्यार्थियों ने लोकतंत्र और मतदान से जुड़े विभिन्न नारों के साथ तख्तियाँ हाथ में लेकर जनजागरूकता फैलाई। विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता एवं मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसे नागरिकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

इस वर्ष महानगरपालिका चुनाव बहु-सदस्यीय पैनल प्रणाली के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं को निर्धारित स्थानों के लिए मतदान करना होता है। इस प्रणाली के बारे में नागरिकों को जानकारी देने के लिए पर्चे वितरित किए जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए जा रहे हैं, डिजिटल माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है, सिनेमा घरों में वीडियो क्लिप दिखाए जा रहे हैं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक नवोन्मेषी उपक्रम लागू किए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकों का उत्साहजनक प्रतिसाद मिल रहा है। इसी कड़ी में कोपरखैरणे क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा रैली निकालकर मानव श्रृंखला बनाने की यह पहल भी अत्यंत सफल और सराहनीय रही।

पश्चिम रेलवे

सिग्नल और टेलीकॉम आउटडोर काम

सीनियर डीएसटीई/नॉर्थ/मुंबई सेंट्रल, दूसरी मंज़िल, डिविज़नल रेलवे मैनेजर का ऑफिस, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-400 008, ई-टेंडर नंबरः SG_216_2_147_WA तारीखः 06-01-2026 आमंत्रित करता है। **काम और जगहः** मुंबई डिवीज़न के विरार-सूरत सेक्शन के करबेली स्टेशन पर मौजूदा गुड्स शेड के दक्षिण में प्लेटफॉर्म के साथ नई गुड्स लाइन के प्रावधान के संबंध में सिग्नल और टेलीकॉम आउटडोर काम। **काम की अनुमानित लागतः** 40,03,013.79. **ईएमडीः** 80,100/-. **ई-टेंडर डॉक्यूमेंट जमा करने की आखिरी तारीख और समयः** 16.02.2026 तक 15:00 बजे। ई-टेंडर खोलने की तारीख और समयः 16.02.2026 को 15:30 बजे। टेंडर वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है। 0984

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, मुंबई सेंट्रल डिवीजन, पश्चिम रेलवे
डिविजनल रेलवे मैनेजर, कमर्शियल डिपार्टमेंट, NFR सेक्शन मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008
काम - मुंबई डिवीजन में विभिन्न NFR मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करना

नीलामी कैटलॉग नंबर	नीलामी शुरू (सभी लॉट)
MMCT-ADVTM25-48	27-01-26 14:00:00

अ. क्र.	लॉट नं0	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की बंद होने की तारीख और समय
1	MSS-BCT-MMCT-MedStn-83-25-1 (Misc-Static-Services - Medical facilities at station)	मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 5 साल की अवधि के लिए इमरजेंसी मेडिकल रूम के ज़रिए चौबीसों घंटे मेडिकल सुविधाएं देना।	1826	27-01-26 14:30:00

नीलामी कैटलॉग नंबर	नीलामी शुरू (सभी लॉट)
MMCT-ADVT-25-69	27-01-26 15:00:00

अ. क्र.	लॉट नं0	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की बंद होने की तारीख और समय
1	ADVT-BCT-BVI-OH-467-26-1 (Advertising - Out of Home)	बोरीवली रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ स्थित प्रवेश-निकास द्वार पर 27 फीट × 9 फीट आकार की एक (1) LCD/LED स्क्रीन स्थापित कर, कुल 243 वर्ग फुट क्षेत्रफल के लिए बुल्क विज्ञापन अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं।	1826	27-01-26 15:30:00
2	ADVT-BCT-BVI-OH-468-26-1 (Advertising - Out of Home)	बोरीवली सर्कुलेटिंग एरिया में 5 साल की अवधि के लिए 20 ग्लोसाइन लगाकर, कुल 592 वर्ग फुट एरिया में बल्क विज्ञापन के अधिकार।	1826	27-01-26 15:40:00
3	ADVT-BCT-MMCT-OH-459-25-1 (Advertising - Out of Home)	मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर 05 साल की अवधि के लिए 28 ग्लो साइन यूनिपोल लगाकर विज्ञापन दिखाने के बल्क अधिकार।	1826	27-01-26 15:50:00
4	ADVT-BCT-MRU-OSN-358-24-1 (Advertising - On Station Premise (Non-Digital))	माटुंगा रोड (MRU) स्टेशन पर 3 साल की अवधि के लिए बल्क विज्ञापन अधिकार।	1096	27-01-26 16:00:00
5	ADVT-BCT-JOS-OSN-449-25-1 (Advertising - On Station Premise (Non-Digital))	जोगेश्वरी (JOS) स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर तीन साल की अवधि के लिए बल्क विज्ञापन अधिकार।	1096	27-01-26 16:10:00
6	ADVT-BCT-GMN-OSN-361-25-1 (Advertising - On Station Premise (Non-Digital))	गोरेगांव (GMN) स्टेशन पर 3 साल की अवधि के लिए बल्क विज्ञापन अधिकार।	1096	27-01-26 16:20:00

संपर्क विवरणः- लैंडलाइन नंबरः- 02267644212, ईमेल आईडीः- acmadvtgbct@gmail.com नोटः इच्छुक बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर ई-ऑक्शन लीजिंग मॉड्यूल पर जाएं। लॉट के अनुसार विवरण वहां बताए गए कैटलॉग में उपलब्ध हैं।
0986

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

अमित साटम का ठाकरे गुट पर तीखा हमला

‘ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो दृश्य दिखाई दिया, वही भविष्य में गिरगांव बीच पर भी दिख सकता है’

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में 7 जनवरी 2026 को मुंबई भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक मान. श्री अमित साटम ने गिरगांव चौपाटी पर एक विशेष पत्रकार परिषद को संबोधित किया। ‘सुरक्षित मुंबई तभी विकसित मुंबई’ विषय पर आयोजित इस पत्रकार परिषद में उन्होंने मुंबई से जुड़े गंभीर मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी।
अमित साटम ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका में 25 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद ठाकरे गुट आज तक अपने किए हुए किसी एक भी ठोस कार्य को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल किया कि जो वादे आज घोषणा-पत्र के माध्यम से मुंबईकरों से किए जा रहे हैं, वे पिछले 25 वर्षों में क्यों पूरे नहीं किए गए? इस अवसर पर उन्होंने मुंबई को प्रभावित कर रही समस्याओं पर आधारित एक प्रेज़ेंटेशन भी प्रस्तुत किया।
इस पत्रकार परिषद में कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढ़ा, भाजपा मुंबई अध्यक्ष श्री अमित साटम, महामंत्री आचार्य पवन त्रिपाठी, श्री राजेश शिरवडकर तथा श्रीमती श्वेता परुळकर उपस्थित थे।
अमित साटम ने कहा, ‘किसी भी शहर की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) जैसी होती है, उसी दिशा में उस शहर का भविष्य और विकास तय होता है। यदि देशविरोधी, आतंकवादी और समाजविघातक शक्तियों को समय रहते नहीं रोका गया, तो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो दृश्य

दिखाई दिया, वही भविष्य में गिरगांव बीच पर भी देखने को मिल सकता है। इसी चेतावनी और जागरूकता के लिए हमने यह पत्रकार परिषद गिरगांव चौपाटी पर आयोजित की है।’
उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना (ठाकरे गुट) पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह चुनाव मुंबई को भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन देने के लिए है। पिछले 11 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार ने जिस प्रकार मुंबई का विकास किया है, उसी तर्ज पर महानगरपालिका का विकास सुनिश्चित करने के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ जल आपूर्ति, उद्यान, फेरीवाला क्षेत्र जैसी मूलभूत सुविधाएं और शहर की सुरक्षा–ये सभी इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। साथ ही, मुंबई के आसपास मंडरा रहे ‘हरे तूफान’ को रोकने का यह निर्णायक चुनाव है।
अमित साटम ने कहा कि वर्ष 1997 से अब तक मुंबई की जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव आया है। हिंदुओं की जनसंख्या 88 प्रतिशत से घटकर 66 प्रतिशत रह गई है, जबकि मुस्लिम समाज की जनसंख्या 8 प्रतिशत से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई में संगठित दबाव समूह सक्रिय हैं और सुनियोजित तरीके से ‘वोट जिहाद’ को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी जमीनों पर अवैध झोपड़ियां बसाकर, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है तथा राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर उन्हें आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र दिलवाए जा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि मालवणी, मालाड, कुर्ला और चांदिवली जैसे क्षेत्रों में 2017 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई है। विशेष रूप से मालवणी-मालाड क्षेत्र में 2024 की लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मात्र चार महीनों में 10 हजार से अधिक मतदाता बढ़े, जो ‘वोट जिहाद’ का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री असलम शेख ने ऐसे तत्वों को संरक्षण दिया।
अमित साटम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बीबीडी चॉल के निवासियों को उसी क्षेत्र में 560 वर्ग फुट के घर उपलब्ध कराना मराठी मानुस के लिए ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। यह न केवल मराठी समाज के पुनर्वास का उदाहरण है, बल्कि उन्हें मुंबई से बेदखल होने से रोकने का मजबूत प्रयास भी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे को खान और शेख जैसे नाम स्वीकार्य हैं, लेकिन देशपांडे और धुरी जैसे मराठी परिवार स्वीकार्य नहीं हैं। संतोष धुरी के पार्टी प्रवेश के बाद यह बात और स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि अपनी समाप्त होती राजनीति को पुनर्जीवित करने के लिए ठाकरे गुट अब देशविरोधी, आतंकवादी और समाजविघातक शक्तियों के साथ हाथ मिला रहा है।
अंत में अमित साटम ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई को भोंगा-मुक्त बनाया गया, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला गया और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी मुंबई की पहचान और स्वरूप को बदलने नहीं दिया जाएगा और देशविरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा।

आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूत करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए-स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर ने निर्देश दिया है कि राज्य के आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में अमरावती, मेलघाट, अकोला, जलगाँव, नंदुरबार, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय के समिति हॉल में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, स्वास्थ्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकावड़े, स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. नितिन अंबाडेकर, संयुक्त निदेशक डॉ. सुनीता गोलहाइट, डॉ. सरिता हजारे शामिल हुए। निदेशक डॉ. विजय कांडेवाड और आदिवासी क्षेत्रों के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। सभी आदिवासी बहुल जिलों में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। अमरावती जिले के ’धारणी’ में स्वास्थ्य संस्थान को अपग्रेड किया जाना चाहिए। खाली पदों को तुरंत भरने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में साफ-सफाई बनाए रखी जानी चाहिए और एक अच्छी भोजन प्रणाली बनाई जानी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर निर्देश दिया।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर निर्देश दिया है कि मेलघाट में एनीमिया उन्मूलन अभियान और सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

डीआरएम कप 2026 क्रिकेट स्पर्धा की शुरुआत

वडोदरा के प्रतापनगर स्थित माधव राव सिंधिया स्टेडियम में आज से डीआरएम कप 2026 शुरु हुआ। इस कप का उद्‌घाटन वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके द्वारा किया गया। भडके ने इस कप में भाग ले रही टीमों के खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया और उन्हें शिद्दत के साथ खेल भावना से अपने सभी मैच खेलने और उन्हें जीतने का आवाहन किया।
इस क्रिकेट कप में वडोदरा मंडल के विभिन्न विभागों एवं? आफिसर्स टीम सहित कुल 16 टीमें क्रिकेट स्प्रिट के साथ भाग ले रही हैं। कप का फाइनल मैच माधव राव सिंधिया स्टेडियम में 20 जनवरी,2025 को खेला जायेगा।

मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल ने उन्नत भिगवण गुड्स शेड में ‘स्टील बार’ की नई हैंडलिंग शुरू की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल ने भिगवण गुड्स शेड में ‘स्टील बार’ की सफलतापूर्वक हैंडलिंग प्रारंभ कर माल ढुलाई विकास पहलों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संचालन क्षमता बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, नव विकसित हैंडलिंग ट्रैक पर क्षेत्रीय विकास कार्य पूर्ण होने के बाद यह प्रगति संभव हो सकी है।
यह माल उतारने का कार्य बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की पहल पर किया गया, जो मंडल की माल ढुलाई श्रेणी के विस्तार और रेलवे-आधारित लॉजिस्टिक्स समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्टील बार से लदी 46 BOSM (ब्रॉड गेज ओपन स्टील वैगन) वैगनों वाली पहली मालगाड़ी जिंदल साइडिंग, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) से भिगवण गुड्स शेड पर प्राप्त हुई।
इन स्टील बार्स की हैंडलिंग बारामती स्थित किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए की गई है, जिससे भिगवण में माल ढुलाई के एक नए प्रवाह की शुरुआत हुई है। अवसंरचना विकास, विशेष रूप से परिसर के उन्नयन से वाहनों की सुगम

आवाजाही और माल की कुशल हैंडलिंग सुनिश्चित हुई है, जिससे माल ढुलाई ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।
माल उतारने के दौरान वाणिज्य, कैरिज एंड वैगन तथा इलेक्ट्रिकल TRD विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने कार्य पर सतत निगरानी रखी और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया। सुरक्षित कार्यप्रणाली पर विशेष जोर दिया गया तथा श्रमिकों को सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्य प्रबंधक, सोलापुर योगेश पाटील ने पुणे, बारामती और सोलापुर क्षेत्र की एमआईडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल) में स्थित औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों से भिगवण के उन्नत गुड्स शेड की सुविधाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
यह पहल अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, ग्राहक-केंद्रित माल ढुलाई सेवाओं तथा सतत विकास की दिशा में सोलापुर मंडल के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। भिगवण गुड्स शेड में स्टील बार की हैंडलिंग शुरू होने से मंडल के माल ढुलाई पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी तथा राजस्व वृद्धि में सकारात्मक योगदान मिलने की अपेक्षा है।

नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबईः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जनवरी माह की इक्कीस से तेईस तारीख तक पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन’ का आयोजन किया जा रहा है। यह तीन दिवसीय सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
यह सम्मेलन अब तक भारत में आयोजित होने वाला लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन से संबंधित सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में स्थित विदेशी दूतावासों के अधिकारी, तथा चुनाव क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और विद्वान भाग लेंगे।
यह सम्मेलन उस दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है, जिसे भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय आईडिया संगठन के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने के पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिकोण का विषय है – समावेशी, शांतिपूर्ण, सशक्त एवं सतत विश्व के लिए लोकतंत्र। यही इस सम्मेलन की मूल अवधारणा है।
भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक राकेश वर्मा ने सम्मेलन की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बताया कि यह सम्मेलन चुनाव प्रबंधन संगठनों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक सशक्त मंच बनेगा। सम्मेलन के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों पर सामूहिक चर्चा, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं एवं नवाचारी पहलों का आदान-प्रदान तथा संयुक्त समाधान विकसित करने का अवसर मिलेगा। इसी अवसर पर सम्मेलन के आधिकारिक प्रतीक चिह्न का भी अनावरण किया गया।
यह सम्मेलन प्रतिनिधियों को भारत की निर्वाचन प्रणाली, चुनावी प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की जानकारी प्रदान करेगा और यह दर्शाएगा कि भारतीय चुनाव व्यवस्था विश्व की लोकतांत्रिक प्रणालियों के लिए एक आदर्श उदाहरण है।
सम्मेलन कार्यक्रम में उद्‌घाटन सत्र, चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों की विशेष बैठक, कार्य समूहों की बैठकें, निर्वाचन आयोग नेटवर्क का उद्‌घाटन, तथा वैश्विक चुनावी मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित विभिन्न विषयगत सत्र शामिल हैं।
तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में विभिन्न देशों के चुनाव निकायों के प्रमुखों के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस सम्मेलन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारतीय जनसंचार संस्थान सहित देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के नेतृत्व में अनेक विषयगत समूह भी इस विचार-विमर्श में सहभाग करेंगे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 70वें रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (एवीआरएसपी) 2025 प्रदान करेंगे

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 मध्य रेल के अधिकारी होंगे सम्मानित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव दिनांक 09 जनवरी 2026 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (यशोभूमि), द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित 70वें रेलवे सप्ताह पुरस्कार समारोह के दौरान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगे।
इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 100 चयनित रेल कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट समग्र प्रदर्शन के लिए जोनल रेलवे को शील्ड भी प्रदान की जाएंगी।
अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के अंतर्गत जोनल रेलवे को शील्ड, जबकि व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं को रजत पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
वर्ष 2025 के लिए मध्य रेल के पाँच अधिकारियों की सेवाओं को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
पुरस्कार विजेताओं का विवरण इस प्रकार हैः

1. मनीष कुमार, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (विद्युत), मुख्यालय, मुंबईङ को वर्ष के दौरान 72 इंजनों के सफल आवधिक ओवरहॉल हेतु कुशल खरीद सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसमें 1,800 से अधिक स्टॉक मदें, जिनकी कुल अनुमानित लागत ?300 करोड़ है, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मानसून की पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने हेतु एक सक्रिय प्रणाली का डिज़ाइन एवं क्रियान्वयन किया तथा 108 निविदाओं और 425 प्रत्यक्ष स्वीकृति मामलों का समयबद्ध निपटान कर संरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मदों की 100इ उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे 2.80 करोड़ की बचत हुई।
2. श्री हिमांशु रामदेव, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (परिचालन), भुसावल मंडलङ को क्रू के लिए यार्ड सिग्नल लेआउट ऐप विकसित करने तथा क्रू के कार्य घंटों की निगरानी हेतु ‘ध्श्ए’ ऐप विकसित करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन नवाचारों से परिचालन दक्षता में सुधार हुआ तथा क्रू से संबंधित विफलताओं एवं ट्रेनों की देरी में 59इ की कमी आई।
3. श्री संजय कुमार बेहरा, मुख्य जांच निरीक्षक, मुख्यालय, मुंबईङ को निवारक जांच करने और साइडिंग पर ओएचई रखरखाव लागत के लिए 47.11 करोड़ रुपये की वसूली का प्रस्ताव देने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा (जो निजी साइडिंग मालिकों द्वारा वहन किया जाना था), जिसमें से 9.78 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं
4. श्री हनुमंत अरुण वाघ, ट्रेन टिकट निरीक्षक, मुख्यालय, मुंबईङ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिना टिकट/उचित टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों के 11,949 मामलों में अकेले ही 84.60 लाख रुपये का जुर्माना वसूल कर बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने के विशेष प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाएगा।
5. श्री प्रद्युमन कुमार, ट्रैक मेंटेनर, नागपुर मंडलङ, को अपनी तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने नागपुर मंडल के नागरी-चिकनी खंड में सुबह की पेट्रोलिंग के दौरान रेल वेल्ड में फ्रैक्चर की पहचान की तथा त्वरित कार्रवाई कर संभावित दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये पुरस्कार अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देते हैं और दूसरों को अपने नियमित कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये पुरस्कार इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि वास्तविक प्रयासों को मान्यता दी जा रही है और अच्छे कार्यों को अनदेखा नहीं किया जाता है।

भुसावल मंडल की आपातकालीन तैयारियाँ सुदृढ़; मनमाड में अत्याधुनिक हाई स्पीड सेल्फ-प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन की प्राप्ति

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आपातकालीन तैयारी एवं आपदा प्रबंधन ढांचे को एक बड़ी मजबूती देते हुए, मध्य रेल्वे के भुसावल मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत अग्रवाल के मार्गदर्शन में मनमाड में अत्याधुनिक हाई स्पीड सेल्फ-प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन प्राप्त की है। इसे रणनीतिक रूप से मनमाड स्टेशन की डबल एग्ज़िट लाइन पर होम किए जाने की योजना है।
यह उन्नत अत्याधुनिक हाई स्पीड सेल्फ-प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन शीघ्र ही पूर्णतः कार्यशील होगी और इसमें जीवन रक्षक एवं आधुनिक बचाव सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें पूर्णतः सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइसेज़, हाइड्रोलिक रेस्क्यू इक्विपमेंट, उच्च तीव्रता वाली प्रकाश व्यवस्था, प्लाज़्मा कटिंग उपकरण तथा एक्सोथर्मिक कटिंग टूल्स शामिल हैं। इसके कमीशन होते ही किसी भी रेल आपात स्थिति में त्वरित, सटीक एवं प्रभावी बचाव तथा राहत कार्य संभव हो सकेगा।
भुसावल मंडल में इस प्रकार की अत्याधुनिक ब्रेकडाउन एवं रेस्क्यू संपत्ति की उपलब्धता से पूरे क्षेत्र में राहत कार्यों की गति, समन्वय और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मनमाड में इसका रणनीतिक स्थान महत्वपूर्ण सेक्शनों तक शीघ्र पहुँच सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रतिक्रिया समय कम होगा और रेल सेवाओं की बहाली तेजी से की जा सकेगी।
सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 (14 जुलाई से 25 सितंबर 2027) के दौरान नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में अपेक्षित भारी यात्री आवागमन को ध्यान में रखते हुए, मध्य रेल्वे के भुसावल मंडल ने व्यापक और केंद्रित सुरक्षा तैयारियाँ की हैं। अत्याधुनिक हाई स्पीड सेल्फ-प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इन तैयारियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने पर यह मजबूत आपात प्रतिक्रिया क्षमता, त्वरित घटना प्रबंधन तथा यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। लाखों श्रद्धालुओं के रेल द्वारा आवागमन के मद्देनज़र, अत्याधुनिक हाई स्पीड सेल्फ-प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन स्थल पर तत्काल चिकित्सा सहायता, अवरोधों की शीघ्र निकासी और रेल सेवाओं की तेज बहाली में सहायक सिद्ध होगी, जिससे रेल परिचालन सुचारु एवं निर्बाध बना रहेगा।

मनमाड में अत्याधुनिक हाई स्पीड सेल्फ-प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का समावेशन भुसावल मंडल, मध्य रेल्वे की सक्रिय, सुरक्षा-केंद्रित एवं दूरदर्शी कार्यप्रणाली को दर्शाता है तथा बड़े राष्ट्रीय एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान भी मजबूत आपदा प्रबंधन और निर्बाध रेल परिचालन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।

क्या है मुंबई का भविष्य! ‘विकास की रफ्तार’ बनाम ‘राजनीतिक स्पीडब्रेकर’

मुंबई(संवाददाता) ।मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक धड़कन और सपनों की नगरी कहा जाता है, आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। पिछले कुछ वर्षों का राजनीतिक घटनाक्रम यह साफ जाहिर करता है कि मुंबई की प्रगति सीधे तौर पर सत्ता की नीयत और नेतृत्व की कार्यक्षमता से जुड़ी है। अब एक बार फिर विकास के दावों और राजनीतिक बहसों के केंद्र में है। जैसे-जैसे बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल शहर के बुनियादी ढांचे को एक प्रमुख चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के समर्थकों का तर्क है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकारों में बड़े प्रोजेक्ट्स को अधिक गति मिली है। उनका कहना है कि जब भी भाजपा-महायुति सत्ता में होती है, मुंबई अपनी पुरानी पहचान ‘दौड़ती मुंबई’ को सार्थक करती है। वहीं दूसरी तरफ महायुति के नेताओं के अनुसारः सड़कों, मेट्रो कॉरिडोर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में देरी का सीधा असर करोड़ों यात्रियों और व्यापार पर पड़ता है। उनका आरोप है कि पिछली सरकारों के दौरान विकास कार्यों में आई बाधाएं तकनीकी या वित्तीय नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित थीं।

फडणवीस कालः मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वर्ण युग
साल 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने मुंबई को आधुनिकता का नया चेहरा दिया। दशकों से फाइलों में दबे प्रोजेक्ट्स जैसे मुंबई मेट्रो नेटवर्क, कोस्टल रोड और अटल सेतु को ’रॉकेट गति’ से जमीन पर उतारा गया। यह वह दौर था जब मुंबई ने वास्तव में वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर कदम बढ़ाए।
महाविकास अघाड़ीः विकास पर ‘ब्रेक’ का दौर
2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर विकास विरोधी होने के गंभीर आरोप लगे। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते मेट्रो-3 के आरे कारशेड को रोकने जैसे फैसलों ने न केवल प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपये बढ़ा दी, बल्कि मुंबईकरों के सफर को भी चार साल पीछे धकेल दिया।
ठहराव की नीतिः जल संरक्षण से लेकर मेट्रो तक, हर जनहितकारी कार्य पर ‘स्थगन’ देना ही MVA की मुख्य नीति बन गई थी। जिस वक्त आम जनता ट्रैफिक और गड्ढों से जूझ रही था

सम्पादकीय

कार्तिगई दीपम विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला सनातन विरोधियों की करारी हार है

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे रोकने का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने साथ ही राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर लगाए गए प्रतिबंधों को निराधार और कल्पनाजन्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि जिस स्थान पर दीपम जलाया जाता है वह मंदिर से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा रहा है। केवल आशंका के आधार पर किसी धार्मिक परंपरा को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल निजी पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि सामूहिक और सार्वजनिक धार्मिक अभिव्यक्तियां भी इसके अंतर्गत आती हैं।

हम आपको बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि दीपम जलाने से सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन का दायित्व भय पैदा करना नहीं बल्कि निष्पक्ष और साहसिक ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि हर परंपरा को संभावित विवाद के नाम पर रोक दिया जाए तो संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता केवल कागज पर रह जाएगी।

हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क रखा गया था कि कार्तिगई दीपम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसे रोकने का प्रयास समाज में अनावश्यक विभाजन और असंतोष को जन्म देता है। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और आदेश दिया कि परंपरागत रीति से दीपम जलाने की अनुमति दी जाए।

देखा जाये तो मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय उस मानसिकता पर करारा प्रहार है जो हर हिंदू परंपरा को कानून व्यवस्था के नाम पर कटघरे में खड़ा करने की आदी हो चुकी है। आज सवाल यह नहीं है कि दीपम जलेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को हर बार डर और शक के चश्मे से देखा जाएगा? तमिलनाडु की द्रमुक सरकार का तर्क कि दीपम जलाने से अशांति फैल सकती है, दरअसल प्रशासनिक असफलता को छिपाने का तरीका है। अगर हर धार्मिक आयोजन से पहले सरकार को डर लगने लगे तो फिर शासन चलाने का नैतिक अधिकार किस बात का रह जाता है? अदालत ने ठीक ही कहा कि कल्पित भय के आधार पर मौलिक अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता। देखा जाये तो यह मामला उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां हिंदू धार्मिक परंपराओं को बार बार रोकने और सीमित करने का प्रयास किया जाता है। कभी शोर का बहाना बनाया जाता है, कभी पर्यावरण का तो कभी कानून व्यवस्था का। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यही तर्क अन्य समुदायों के मामलों में अचानक गायब हो जाते हैं। यह दोहरा मापदंड समाज में असंतोष और अविश्वास को जन्म देता है।

कार्तिगई दीपम का सामाजिक महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है। यह पर्व सामूहिकता का प्रतीक है। पहाड़ी पर जलता दीप दूर दूर तक दिखाई देता है और समाज को जोड़ने का काम करता है। जब ऐसी परंपराओं को रोका जाता है तो संदेश जाता है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाएं गौण हैं। यही भावना धीरे धीरे आक्रोश में बदलती है और फिर वही आक्रोश सामाजिक तनाव का रूप ले लेता है। इस फैसले का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि लोगों का यह विश्वास और प्रबल हुआ है कि न्यायपालिका संविधान की आत्मा को समझती है। अदालत के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य केवल एक धर्म के प्रति कठोर हो जाए और बाकी के प्रति नरम। सच्ची धर्मनिरपेक्षता सभी परंपराओं के साथ समान व्यवहार की मांग करती है। यह निर्णय प्रशासन के लिए भी चेतावनी है। उसे समझना होगा कि परंपराओं को दबाने से शांति नहीं आती बल्कि असंतोष भीतर ही भीतर सुलगता रहता है।

शिक्षा का स्वदेशीकरण : विकसित भारत के सपने को हकीकत बनाने की आधारशिला

विकसित भारत की लक्ष्य-साधना निश्चित रूप से देश के हर नागरिक को प्रोत्साहित करेगी। आज के वैश्विक अस्थिरता के माहौल में ऐसा कौन होगा, जो भारत को विकसित होते न देखना चाहे! भारत के संविधान निर्माताओं ने उस समय चौदह साल तक के हर बच्चे को अगले दस वर्षों में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। वे सभी देश की सामर्थ्य की वास्तविकता से अवगत थे, मगर यह भी जानते थे कि बड़े लक्ष्य जो प्रेरणा देते हैं, वे बहुत दूर तक ले जाते हैं।

समय ने इसे सिद्ध किया है, हालांकि लक्ष्य अभी भी कहीं न कहीं अपनी दूरी दर्शाता है। लक्ष्य-साधना की सफलता के लिए यह मानकर ही चलना होगा कि इसके लिए सार्वभौमिक स्तर पर देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक होगा। जो कमी दिखेगी, उस पर भी सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता को और अधिक सशक्त बनाकर सफलता के द्वार खोले जा सकते हैं। अतः इन दोनों पक्षों को सरकारी प्रयासों में भी प्रमुखता देनी होगी, लेकिन उसके लिए समाज तथा शिक्षा संस्थानों का योगदान सर्वोपरि होगा।

भारत में अधिकांश अध्यापक बहु-जातीय और बहु-पंथिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं तथा वे स्वयं भी ऐसी ही कक्षाओं में पढ़कर आए होते हैं। विविधता को साझा करने का ऐसा संजोग शायद ही कहीं और इतनी प्रचुरता से मिलता होगा! भारत की प्राचीन ज्ञानार्जन परंपरा की गहराई, सूक्ष्मता और वैश्विकता में निहित 'सर्वभूत हिते रतः' की भावना का सम्मान भी सर्वत्र होता है। जहां पूर्वाग्रह बौद्धिकता को ढ़क लेते हैं, वहां

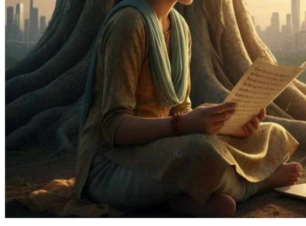

ऐसा नहीं हो पाता है।

विश्व में हर प्रकार की विविधता के सम्मान की जो व्यावहारिक अवधारणा भारत में पनपी है, और जो आज भी जीवंत है, वैसी अन्य कहीं नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता आंदोलन में देश ने अच्छी तरह समझ लिया था कि भारतीयों को बांटने, और अंततः देश का विभाजन करने में ब्रिटिश शासन ने कैसे-कैसे हथकंडे अपनाए थे। सबसे सशक्त साधन तो उनको 1835 में थामस बैबिंगटन मैकाले ने प्रदान किया था। उन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जो योजन बनाई, उसका लक्ष्य उनके लिए पूरी तरह स्पष्ट थाः 'हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं, जो खून और रंग में भारतीय होंगे, मगर रुचि, राय, नैतिकता और बौद्धिकता में अंग्रेज होंगे।'

मैकाले की भारत, उसकी संस्कृति और वैश्विक ज्ञान भंडार में उसके योगदान के संबंध में जो राय थी, उसे याद करने से यह समझ में आ जाएगा कि भारतीयों को सूरत से भले ही न सही, दिल से अंग्रेज बना देने में अपनी सफलता के प्रति वह इतना आश्वस्त क्यों था! मैकाले ने भारत की सुव्यवस्थित ज्ञानार्जन प्रणाली और नए ज्ञान की जनहित में उपयोगिता के लिए शोध के प्रति समर्पण की परंपरा को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंपरागत स्कूलों और संस्थाओं को उसने यह कहकर नकार दिया कि उन पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा, जबकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्कूलों में लोग अच्छी-खासी फीस देकर आने को तैयार रहते हैं। ऐसा आज भी देश में हो रहा है, और यह लगातार बढ़ रहा है।

स्वतंत्रता के बाद तीन-चार दशकों में न जाने कितने बच्चों ने स्कूल कुछ वर्ष बाद केवल अंग्रेजी सीखने में असफल होने के कारण छोड़ दिए थे। धीरे-धीरे वह स्थिति बदली है, लेकिन आज भी अधिकांश सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। कहा नहीं जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृ भाषा पर दिए गए जोर के बावजूद स्थानीय स्तर पर भी नौकरियों में अंग्रेजी का प्रभाव भाषागत भेदभाव का कारण नहीं बनेगा!

वैसे लोग अब घरों में रखे जाने वाले सहायक एवं सहायिकाओं से भी अपेक्षा करते हैं कि उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो, वे 'माल' से सामान मंगा सकें, उसमें मियाद की तारीख पढ़ सके! मैकाले की दूरदृष्टि और भविष्य के आकलन की क्षमता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, क्योंकि वह भारतीयों को भारत से अलग करने में कितना सफल रहा, इसे हम आज भी देख रहे हैं। हम आजादी के बाद भी मैकाले के बिछाए जाल से नहीं निकाल पाए, तो इसमें दोष हमारा ही है!

वैसे भी अब समय मैकाले की आलोचना का नहीं, बल्कि भारतीयों को भारत से पुनः पूरी तरह जोड़ने का है। संभवतः ऐसे ही विचार सर्वोच्च स्तर पर नीति निर्धारकों के भी रहे होंगे, तभी तो देश को मैकाले के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करने का आह्वान किया गया है। यह भी स्वीकारोक्ति है कि 1835 में मैकाले ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें जमाने के लिए जिस शिक्षा व्यवस्था को तत्कालीन स्वदेशी प्रणाली को नष्ट कर लागू किया, उसके प्रभाव से भारत आज भी मुक्त नहीं हो पाया है।

यह भी एक तथ्य है कि अनगिनत अवसरों पर संसद में चर्चाएं हुई थीं, आश्वासन दिए गए और प्रयास भी हुए, लेकिन बात बनी नहीं! इसका कारण अज्ञात नहीं है, मगर वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसका पुनः विश्लेषण आवश्यक हो गया है। इसके लिए फिर से अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत को स्वीकार करना होगा। हावर्ड विश्वविद्यालय की ख्याति विश्वव्यापी है और उसे ज्ञान के प्रसार, प्रचार एवं संवर्धन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। यहां के दो पुराने छात्र हेनरी डेविड थोरो और राल्फ वाल्डो एमरसन अपने बौद्धिक ज्ञान और उसके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। एक बार दोनों अपनी पुरानी मातृ संस्था को लेकर चर्चा कर रहे थे।

एमरसन ने कहा कि अब इस विश्वविद्यालय में ज्ञान की सभी शाखाएं स्थापित हो चुकी है और प्रगति कर रहीं हैं। थोरो ने उत्तर दिया- शाखाओं की बात अति सुंदर है एवं उत्साहजनक है, लेकिन जड़े कैसी हैं, यह जानते रहना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक संरचना को गति और मजबूती देने के लिए सबसे पहले उसकी नींव के टिकाऊ आधार-स्तंभों को जानना और समझना आवश्यक है, ताकि इनके ऊपर आगे की संरचना आधुनिक वैश्विक संदर्भ में निर्मित की जा सके। भारतीय दर्शन में शिक्षा प्रणाली में विद्या, ज्ञान, मेधा, बुद्धि का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है, जो नैतिक कसौटी पर भी पूरी तरह खरे उतरें।

भविष्य के भारत की शिक्षा नीतियां केवल ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण न करें, जो जीवन में सिर्फ धनार्जन और सुख सुविधाओं के संग्रहण को ही शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मान ले या जिन्हें जीवन के उच्चतम लक्ष्यों और उससे प्राप्त होने वाले 'सत्, चित, आनंद' के संबंध में जानकारी न हो, और न ही इसे लेकर कभी कोई प्रेरणा मिली हो। बेहतर शिक्षा से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा में मानवीय मूल्यों का होना भी जरूरी है, तभी सामाजिक चेतना का निर्माण होता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कारों की परंपरा व्यक्ति को उसकी आत्मा की उपस्थिति, गरिमा और उसकी विश्व व्यापकता का भान कराती है। यह पद्धति संस्कारों को जीवन-प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्त्व मानती है। इसी से व्यक्ति में सत्य और अन्याय की समझ बढ़ती है तथा इसकी खोज में जीवन लगाने में आनंद का आभास होता है।

महिला अपराधों पर समाज का दोहरा रवैया और चुनिंदा आक्रोश

हाल के दिनों में वर्ष भर की चर्चित राष्ट्रीय घटनाओं, दुर्घटनाओं की यादों की पुनरावृत्ति के क्रम में एक पति की हत्या करके ड्रम में डाल देने और हनीमून मनाने के क्रम में हत्या की बहुप्रचारित दो घटनाओं की खूब चर्चा की गई। ये भी कहा गया कि इन दोनों मामलों ने समाज में वैवाहिक रिश्तों की सुरक्षा, भरोसे और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। निश्चित रूप से ये दोनों घटनाएं भयावह थीं।

इस अपराध में शामिल महिलाओं ने न सिर्फ दो निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके माता-पिता और परिवार को जीवन भर का दर्द दिया, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं को भी तार-तार किया। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि जब उन्हें उक्त वैवाहिक बंधनों को निभाना नहीं था, तो विवाह नहीं करना चाहिए था।

हालांकि जीवन और परिस्थितियों के अपने-अपने संदर्भ होते हैं और घटनाएं भी उसी मुताबिक संचालित होती रहती हैं। उसमें दूसरों की राय के लिए बहुत जगह नहीं होती। मगर इन बातों को आज के बिगड़ती सामाजिक बनावट, खराब माहौल, स्वतंत्रता की परिभाषा, मोबाइल और सोशल मीडिया के भयानक तरीके से जीवन में घुसपैठ, सांस्कृतिक क्षरण आदि के रूप में देखा जा सकता है। इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई हैं।

टीवी चैनलों ने बहस और चर्चा भी परोसी। महीनों तक हर तरफ घरों, मोहल्लों, चौक-चौराहों यही मुद्दा छाया रहा। पूरी महिला बिरादरी इसके लपेटे में आई और गाहे-बगाहे उन्हें तीखी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। जो हुआ, वह निश्चित तौर पर बुरा था और पूरे समाज ने इसके विरोध में जिस तरीके से एकजुटता दिखाई, वह गौरतलब थी।

इसके समांतर कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल, जो इन शोरगुल के बीच दबे रह गए या किसी ने उठाया भी तो लोगों को गौरतलब ही नहीं लगा, वह यह है कि क्या ये दोनों मामले 'वैवाहिक हत्याओं' के संदर्भ में इकलौते हैं? क्या कभी लड़कियों की दहेज, अवैध संबंध, झूठे सम्मान के नाम पर हत्या अन्य मुद्दों को लेकर ऐसी ही या इससे भी विद्रूप नृशंस हत्याएं नहीं की गई हैं?

सामूहिक बलात्कार, तेजाबी हमले से मारी जाती, अपंग होती लड़कियों के मामलों पर कभी इतना शोर क्यों नहीं हुआ? कम या ज्यादा उम्र में बलात्कार का दंश भोगती, प्रताड़ित होती, मौत की ओर धकेली जाती अनगिनत महिलाओं के सच को जानकर भी समाज ने अब तक क्या किया है?

हमारे इर्द-गिर्द हर रोज होती ऐसी घटनाएं और साल दर साल महिला उत्पीड़न के बढ़ते आंकड़ों का सच आखिर क्या है? प्रश्न यह भी कि चंद अपवादों की बात छोड दें, तो क्या दूसरा पक्ष भी परंपराओं, कट्टरता और आपराधिक प्रवृत्ति के त्रास तले उतना ही दंड भोग रहा है? ऐसे तमाम आपराधिक कृत्य हर रोज, हर तरफ होते हैं, तो फिर कुछ घटनाओं की तरह सामाजिक एकजुटता इन पर क्यों नहीं दिखाई जाती? संभव है, वैसी ही एकजुटता महिला उत्पीड़न के बढ़ते आंकड़ों की दर को कुछ कम कर देती। यहां आशय लैंगिक आधार पर अपराधों को कम या ज्यादा करके आंकना कतई नहीं है, क्योंकि अपराधी चाहे महिला हो या पुरुष, उसकी प्रवृत्ति सिर्फ अपराध करने की होती है। पीड़ित भी सिर्फ पीड़ित होता है। वर्ग या रसूख के आधार पर अन्याय तथा अनाचार का बंटवारा करना और न्याय का पलड़ा उसके अनुसार मोड़ना अपने आप में एक बड़ी खामी है।

आज के कथित आधुनिक समाज में भी स्त्री को पल प्रति पल अनगिनत मानसिक और शारीरिक

अपराधों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति बाहर के साथ-साथ अक्सर घर में भी होती है। कभी मिथ्या सामाजिकता और संस्कृति बचाए रखने, कभी पारिवारिकता को बनाए रखने, कभी प्रचलित फिजूल की परंपराओं के सम्मान में, तो कभी सुरक्षा के नाम पर स्त्री को असंख्य आपराधिक कृत्यों का सामना करना पड़ता है।

शादी के बाद परिवार के भीतर और खासतौर पर पत्नी के प्रति पति के निजी व्यवहार तो हमारे समाज में कभी बहस का विषय रहे ही नहीं हैं। ऐसे उत्पीड़न को आमतौर पर प्यार का नाम देकर बड़ी आसानी से छुटकारा पा लिया जाता है। ज्यादातर महिलाओं ने इसे सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया है।

अधिकांश परिवार आज भी उसी पुरातन सोच पर कायम है कि बेटियां जिस घर में ब्याही जाती हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वही उनका अपना घर होता है। यही सोच लड़कियों को सब कुछ सहकर ससुराल में रहने के लिए विवश करता है। परिवार भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें ऐसा करने को मजबूर करता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोचने-समझने के ढांचे और मानस में घुली सोच की होती है, जिससे छुटकारा पाना केवल साहस और दखल के बूते संभव है, लेकिन इसमें बेटियों की संपत्ति में हिस्सेदारी का डर एक बड़ी भूमिका निभाता है।

चूंकि तमाम कानूनों के बावजूद अभी भी पिता की संपत्ति पर व्यवहार में सिर्फ बेटों का ही अधिकार होता है और ससुराल की संपत्ति तो बेटियों की होती ही नहीं है, तो ऐसे में आर्थिक रूप से पराश्रित लड़कियां मृत्युपर्यंत सब कुछ सहने को अभिशप्त होती हैं। अगर वे आवाज उठाती भी हैं तो 'घर तोड़ने वाली' महिला जैसी संज्ञा से नवाजी जाती हैं। इस तरह की सारी परिस्थितियां स्त्रियों की चुप्पी का कारण बनती हैं।

हमारा समाज भी स्त्रियों के अनुपयोगी होने की अपनी धारणा के अनुसार उनके साथ होने वाले तमाम अत्याचारों, यहां तक की मृत्यु पर भी मौन की खाल ओढ़े रहता है। कुछ खास और चर्चित घटनाओं में हत्याओं पर होने वाला शोर और शेष पर मौन उसी का हिस्सा है।

अमेरिका के इशारे पर न थिरकने वाले देश कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें!

अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से संपन्न अमेरिका अपनी 'डीप स्टेट खलनीति' के बल पर दुनिया का दादा बन चुका है। चूंकि जी-7 के देश उसके मजबूत हाथ हैं, इसलिए ब्रिक्स देशों की औकात उससे खुलेआम उलझने की आजतक नहीं बन पाई है। आखिर पहले भारत के पास-पड़ोस में, फिर ईरान में और अब बेनेजुएला के दास्तान जो चुगली कर रही हैं, उसके वैश्विक मायने तो यही हैं। अब अगला नम्बर शायद कम्बोडिया का आएगा, जिसे ट्रंप ने ताजा धमकी दी है।

देखा जाए तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्वप्नद्रष्टा डॉनल्ड ट्रंप उनकी मुद्रा को चुनौती दिलवाने वाले, यदा कदा उनको आंखें दिखाने वाले रूस-चीन के मजबूत समर्थकों के एक एक कर रीढ़ तोड़ने और इसी झांसे में जांबाज भारत को धमकाकर अपने खेमे में मिलाने के लिए सधी चालें चलना शुरू कर चुके हैं। डीप स्टेट से जुड़े लोगों की मानें तो आगे अमेरिका अभी बहुत कुछ करने वाला है। इस बात का संकेत कभी न्यूयॉर्क के महापौर ममदानी और भारतीय-अमेरिकी आशा जडेजा के इशारों से चलता है। ममदानी जहां खुलेआम स्वजातीय भारतीय देशद्रोहियों के पक्ष में खत लिख रहे हैं, वहीं आशा जडेजा ने तो खुलेआम भारत को रूसी सम्बन्धों पर नसीहत दी है।

मतलब साफ है कि दुनिया भर में ब्रिक्स और रिक (रूस-भारत-चीन) देशों का हौव्वा खड़ा करके रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कभी अलग अलग और कभी संयुक्त मंच पर अमेरिका विरोधी शेखी बघारते आये हैं, उनके ग्लोबल साउथ के सपनों पर बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी है। यदि डीप स्टेट के समक्ष ट्रंफ ने घुटने टेके हैं तो अब उन्हें रणनीतिक बुलंदी भी मिल रही है। रूस को यूक्रेन में, भारत को पाकिस्तान-बंगलादेश से और चीन को दक्षिण चीन सागर में उलझाए रखने की जो खतरनाक अमेरिकी साजिश है, उसकी काट अभी किसी के पास नहीं है।

अभी तक एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में अमेरिका को कमजोर करने की जो चालें चीन व भारत की तरफ से अलग अलग चली जा रही थीं, इनकी हवा निकालने के लिए ही अमेरिका ने अपना आक्रामक तेवर दिखा दिया है, जिसे रोकना अब किसी के बूते की बात नहीं। सच कहूं तो अमेरिका ने 19वीं शताब्दी से ही अपना विरोधी रहे कई देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता परिवर्तन करवाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, एशिया और मध्य-पूर्व के देश शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि वाकई ये हस्तक्षेप अक्सर डीप स्टेट के इशारे पर सीआईए के माध्यम से गुप्त अभियानों, सैन्य आक्रमणों या समर्थन के जरिए हुए। इस बात को स्पष्ट करने वाले कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण निम्नलिखित हैं, जो अमेरिका के विरोधी देशों को अपने हद में रहने की खुली नसीहत देते हैं। चाहे अमेरिका का पुराना प्रतियोगी सोवियत संघ हो या फिर उसके अवशेष पर खड़ा रूस और उसका नया वैश्विक पार्टनर चीन, अमेरिका के नापाक इरादों में कभी मजबूत बाधक नहीं बन पाए।

मसलन, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी अंतर्राष्ट्रीय विवशता जगजाहिर हो चुकी है। यह स्थिति जहां एकध्रुवीय विश्व की अमेरिका परिकल्पना और उसकी दादागिरी को परिपुष्ट करती है। वहीं, बहुध्रुवीय विश्व के पैरोकारों रूस, चीन और भारत आदि की नीतिगत बेचारगी की बखिया उधेड़ देती है। आइए अमेरिकी षड्यंत्र की साल दर साल मिली सफलता पर एक नजर डालते हैं। पहला, 1953 में ईरान में मोहम्मद मोसद्देघ की सरकार को अमेरिका के इशारे उखाड़ फेंका गया, और शाह को सत्ता में लाया।

दूसरा, 1954 में ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति जैकोबो आरबेंज को हटाया गया और कार्लोस कास्टिलो आर्मास को सत्ता दी गई। तीसरा, 1963 में दक्षिण वियतनाम में राष्ट्रपति न्गो दिन्ह दीम की हत्या में सहायता दी। चतुर्थ, 1973 में चिली में सल्वाडोर एलेन्डे को उखाड़ा, और ऑगस्टो पिनोशे को सत्ता सौंपी। पांचवां, 1983 में ग्रेनाडा में सैन्य आक्रमण से सरकार बदली। छठा, 1989 में पनामा में मैनुअल नोरिएगा को हटाया। सातवां, 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन शासन को समाप्त कर उन्हें फांसी पर लटकवाया।

आठवां, 2011में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के पतन में सहयोग दिया। नवाँ, 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाया और कम्बोडिया के राष्ट्रपति को धमकाया। दरअसल, ये सूची प्रमुख मामलों तक सीमित है; जबकि कुल 80 से अधिक ज्ञात अमेरिकी हस्तक्षेप हुए हैं।

हैरत की बात है कि अमेरिका के विरोधी देशों ने उसके सत्ता परिवर्तनों पर अक्सर खामोशी साधी या सीमित विरोध किया, क्योंकि सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक शक्तियों का असंतुलन उन्हें प्रत्यक्ष टकराव से रोकता था। सोवियत संघ जैसे प्रतिद्वंद्वी भी कई मामलों में अपनी सीमाओं के कारण सक्रिय हस्तक्षेप से परहेज करते रहे। वह सिर्फ भारत के मामले में ही कामयाब हो पाया, जहां अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-

पहला, सैन्य श्रेष्ठताः अमेरिका की परमाणु क्षमता और विशाल सेना ने विरोधियों को जोखिम लेने से रोका, जैसे चिली (1973) में सोवियत संघ ने केवल निंदा की। दूसरा, आर्थिक निर्भरताः कई देश अमेरिकी सहायता या व्यापार पर निर्भर थे, जिससे खुला विरोध अव्यवहारिक था। तीसरा, क्षेत्रीय प्रभावः लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभुत्व (मुनरो सिद्धांत) विरोध को अप्रभावी बनाता था। इसलिए सामरिक प्रतिक्रियाएं नगण्य रहीं। चतुर्थ, प्रतिसादः विरोधी देशों ने खुद गुप्त सहायता दी, जैसे क्यूबा ने अंगोला में हस्तक्षेप किया। पांचवां, कूटनीतिः संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए गए लेकिन वीटो के कारण विफल रहे। छठा, आंतरिक प्राथमिकताएंः चीन-रूस जैसे देशों की अपनी घरेलू चुनौतियां सक्रिय विरोध को सीमित करती रहीं।

हैरत की बात तो यह है कि अब रूस और चीन की तरह ही गुटनिरपेक्ष देश भारत को भी अमेरिकी नसीहत मिल रही है, जो गम्भीर बात है। गत दिनों जब वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले ने दुनिया का ध्यान खींचा है तो इस घटनाक्रम पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दुनियाभर से सामने आ रहे हैं। इसी बीच भारतीय-अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा मोटवानी ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत पर तंज कसा है।

आशा ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस से बहुत सारे हथियार खरीद रखे थे। हालांकि जब अमेरिका ने हमला किया तो ये हथियार काम नहीं आए। अमेरिकी सैनिक मादुरो तक पहुंचे और उनको बंधक बनाकर अमेरिका ले आए। ऐसे में भारत को भी इससे सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि भारत के पास भी ज्यादातर रूस के ही हथियार हैं।

आशा मोटवानी ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा, 'वेनेजुएला के रूसी मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिकी मिलिट्री के सामने कुछ सेकंड में टूट गए। उम्मीद है भारत देख रहा होगा। हमारे लिए यह जानना समझदारी होगी कि हमारी रोटी का कौन सा हिस्सा मक्खन लगा हुआ है, कौन हमारे ताकतवर दोस्त हैं और कौन नहीं।' अपनी पोस्ट में आशा ने भारतीय अमेरिकियों और भारतीय रूसियों की संख्या के अंतर को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हुए एक गलत आंकड़ा दिया- 'भारतीय अमेरिकीः 5, 000, 000। भारतीय रूसीः 5।'

दरअसल, भारतीय मूल की वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा हालिया समय में अमेरिका में चर्चा में आती रही हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने [illegible] पर अपना रुख बदला था। सिलिकॉन वैली की वेंचर कैपिटलिस्ट आशा डानाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा दान देने वाले लोगों में शुमार हैं। आशा जडेजा मोटवानी ने 200 से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स में निवेश किया है। उनके प्रमुख निवेशों में गूगल, पिंटरेस्ट, यूलू, क्रेडलवाइज, एडहैक टेक्नोलॉजीज, क्लिमैक्टिक और नेशनल एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक नर्स प्रैक्टीशनर्स शामिल हैं। आशा के पति राजीव मोटवानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। 2001 में उन्हें गोडेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

डीएलएड में आनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश तय, कुल सीटों के सापेक्ष आधे हुए है आनलाइन आवेदन

आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी पहले चरण में स्टेट रैंक के आधार पर 12 से संस्थान का भरें विकल्प

प्रयागराज। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) - 2025 में प्रवेश के लिए संस्थान के विकल्प वेबसाइट- updeled.gov.in के माध्यम से भरे जाएंगे। सबसे बडी बात यह है कि डीएलएड में कुल 2.39 लाख सीट है जबकि इस बार आनलाइन 1, 24, 230 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है ऐसे में काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित है।

उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से रजिस्ट्रार ने समय सारिणी जारी कर दी गयी है। प्रवेश प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। आवेदन करने वाले सभी 1, 24, 230 अभ्यर्थी पहले चरण में स्टेट रैंक के आधार पर 12 जनवरी से संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। स्टेट रैंक आठ जनवरी को वेबसाइट पर जारी की जाएगी। स्टेट रैंक एक से 20, 000 तक के अभ्यर्थी 12 जनवरी से 14 जनवरी तक संस्थान का विकल्प चुन सकेंगे, जिन्हें 15 जनवरी को कालेज / संस्थान आवंटित किया जाएगा। रैंक 20, 001 से 70, 000 तक के अभ्यर्थी 15 जनवरी शाम से 18 जनवरी तक विकल्प भरेंगे, जिन्हें संस्थान 19 को आवंटित होगा।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इस अवधि में रैंक 20, 000 तक विकल्प ना पाने वाले व जिन्हें संस्थान आवंटित न हुआ हो, वह अभ्यर्थी भी विकल्प भर सकेंगे। इसके बाद 19 जनवरी शाम से 22 तक रैंक 70, 001 से 1, 24, 230 तक के आवेदक संस्थान चुनेंगे। इन्हें 23 को संस्थान आवंटित होगा। यह सभी 17 से 30 जनवरी शाम पांच बजे तक प्रवेश ले सकेंगे। दूसरे चरण में पांच फरवरी शाम से आठ फरवरी तक अन्य राज्य के आवेदक अभ्यर्थी तथा आरक्षित श्रेणियों के प्रवेश न पाने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी भी संस्थान का विकल्प चुन सकेंगे, जिन्हें संस्थान नौ फरवरी को आवंटित किया जाएगा।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि इसी तरह नौ फरवरी शाम से 12 फरवरी तक सभी आवेदकों को अवसर देने के बाद आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त सीटों को अनारक्षित में परिवर्तित कर 13 फरवरी को कालेज आवंटित किया जाएगा। यह अभ्यर्थी 11 से 21 फरवरी शाम पांच बजे तक प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों के साथ कालेज में उपस्थित होना होगा। शुल्क सहित प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा -निर्देश पढ़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि शुल्क वापसी नहीं की जाएगी।

सपा के महानगर इकाई की मासिक बैठक सम्पन बैठक में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने को लेकर बनी ठोस रणनीति

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई की मासिक बैठक आज पार्टी कार्यालय जार्ज टाउन में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सैयद इफ़्तेख़ार हुसैन एवं संचालन महासचिव रविन्द्र यादव एडवोकेट ने किया।

बैठक में चर्चा करते हुए नेताओं ने कहा कि एिंं (एजर्मेंत घ्ह्लहेर्न्ंन्गिदह) के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे युवा, महिलाएं एवं वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए मतदाता सूची का समावेशी होना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

बैठक में महानगर अध्यक्ष सैयद इफ़्तेख़ार हुसैन द्वारा बताया गया कि चुनाव आयोग से प्राप्त फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर पात्र नागरिकों की पहचान करेंगे, उन्हें फॉर्म-6 भरने में सहयोग करेंगे और समयबद्ध ढंग से संबंधित निर्वाचन कार्यालयों में फार्म जमा कराएंगे। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं, नवविवाहित महिलाओं तथा हाल ही में स्थानांतरित हुए नागरिकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

बैठक को संबोधित करते हुए एमएलसी एवं महानगर प्रभारी डॉ मानसिंह यादव ने कहा कि यह कार्य केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है। समाजवादी पार्टी हमेशा से जनभागीदारी और सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना नागरिक अधिकारों की रक्षा का एक सशक्त माध्यम है। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर की तीनो

विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों की मतदाता सहायता टीम का गठन किया गयाहै जो फॉर्म-6 से संबंधित जानकारी, दस्तावेजों की जांच तथा ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन में मदद करेगी। साथ ही, पार्टी के वरिष्ठ नेता समय-समय पर इस अभियान की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में सर्व श्री सैयद इफ़्तेख़ार हुसैन, डॉ मानसिंह यादव, रविन्द्र यादव, शशांक त्रिपाठी, मो शारिक, तारिक सईद अज्जू, मोईन हबीबी, कमला यादव, वजीर खान, महबूब उस्मानी, मो गौस, दान बहादुर मधुर, आर एन यादव, सचिन श्रीवास्तव, बबलू रावत, संतोष, देवीलाल, रवि गुप्ता, रेहान अहमद, तहजीब, अहमद राजा, अजय यादव, भोला पाल, माशाहद, सऊद अहमद, लाल चंद्र कुशवाहा, महेंद्र निषाद, मृतुन्जय, शकील आदि सहित भारी संख्या में कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

संतों ने किया पांडेश्वर नाथ की महिमा का बखान पंचकोसी परिक्रमा पांडेश्वर नाथ धाम पहुंची

थरवई। सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं से जन-जन को जोड़ने के उद्देश्य से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा निकाली जा रही पंचकोसी परिक्रमा गुरुवार को पांडेश्वर नाथ धाम पहुंची। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं जूना अखाड़ा के संरक्षक महंत हरि गिरी महाराज के नेतृत्व में संतों का जत्था यहां पहुंचा।पांडेश्वर नाथ धाम पहुंचने पर सभी पूज्य संतों द्वारा विधि-विधान से मंदिर में दर्शन-पूजन किया गया। इस अवसर पर महंत हरि गिरी महाराज ने पांडेश्वर नाथ की महिमा का बखान करते हुए कहा कि अज्ञातवास के समय पांडवों द्वारा इस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की गई थी, जिसके कारण इस शिवलिंग की विशेष और व्यापक महिमा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू को अपने-अपने मंदिरों के संरक्षण और नियमित पूजा-अर्चना के लिए आगे आना चाहिए।महंत हरि गिरी महाराज ने कहा कि तीर्थ स्थलों से आत्मीय जुड़ाव व्यक्ति के अंतर्मन को पवित्र करता है। सनातन धर्म से जुड़े तीर्थों से दूरी तथा धर्म और संस्कारों के प्रति उदासीनता सदियों से हिंदू समाज के लिए चुनौती बनी हुई है।जूना अखाड़ा के सभापति महंत प्रेम गिरी महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अखाड़ा परिषद द्वारा प्रयागराज के समस्त तीर्थ स्थलों की पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ किया गया है, जिससे धर्म और संस्कारों के प्रति जनजागरण हो सके।इस दौरान पांडेश्वर नाथ धाम के महंत देवेंद्र गिरी महाराज द्वारा सभी पूज्य संतों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। परिक्रमा के आगमन से पांडेश्वर नाथ धाम में भक्तिमय वातावरण बना रहा।

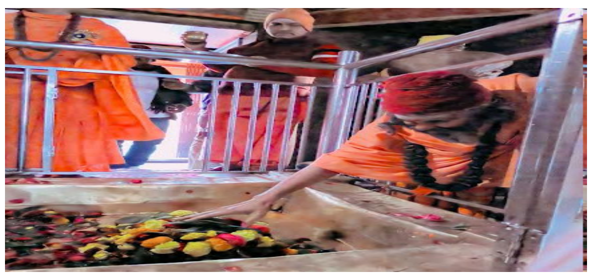

पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मश्रम महराज की भागवद् कथा 15 से

प्रयागराज। अखिल भारतीय दण्डी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मश्रम महराज का शिविर माघ मेला के सेक्टर - 6 ओल्ड जीटी रोड दक्षिणी पटरी पर लगा हुआ है। शिविर के व्यवस्थापक आचार्य कपिल शास्त्री ने आज बताया कि पौष पूर्णिमा से शिविर में सुबह पांच बजे से जलपान, चाय, दोपहर से अन्न क्षेत्र देर शाम तक चल रहा है जो माघी पूर्णिमा तक चलता रहेगा। इस दौरान बडी संख्या में श्रद्धालु, शिष्य सहित मेला क्षेत्र में कार्य करने वाले बडी संख्या में लोग भी भण्डारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे है। उन्होंने बताया कि वृन्दावन के आचार्य सदानंद जी की भागवद कथा सुबह 10 बजे से शुरू हो गयी है। अखिल भारतीय दण्डी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मश्रम महराज की श्रीमद भागवद कथा 15 जनवरी से दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक कथा होगी। 22 जनवरी से कानपुर के आचार्य सोमदत्त की श्रीमदभागवद कथा दोपहर एक बजे से शुरू होगी।

'मिशन शक्ति 5.0' अभियान : महिलाओं एवं बालिकाओं को किया जागरूक

प्रयागराज। जोन यमुनानगर के समस्त थानों की मिशन शक्ति /एंटी रोमियो टीम द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति 5.0' अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं को नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन का संदेश देते हुए किया गया जागरूक। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज महोदय व अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज महोदय के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के कुशल पर्यवेक्षण में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत जोन यमुनानगर के समस्त थानों की मिशन शक्ति /एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बालिकाओं व महिलाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह योजना, चिकित्सा संबंधी आयुष्मान योजना व हेल्पलाइन नंबर जैसे- वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर की दी जानकारी।

कलर्स आफ कल्चरल एंड आर्ट फाउंडेशन के पदाधिकारियों का हुआ गठन

आशीष हुए अध्यक्ष महामंत्री बने राहुल कुमार

प्रयागराज। कलर्स आफ कल्चरल एंड आर्ट फाउंडेशन की बैठक मुंशी राम प्रसाद की बगिया मुट्ठीगंज में आयोजित किया गया इस अवसर फाउंडेशन के पदाधिकारियों का गठन किया गया

इस अवसर फाउंडेशन के संरक्षक राजेश केसरवानी एवं रमेश अग्रहरि ने आशीष कुमार गुप्ता को अध्यक्ष एवं महामंत्री राहुल कुमार को घोषित किया इसके अलावा उपाध्यक्ष संजीव कुमार एवं अंशू दीप धुसिंया, कोषाध्यक्ष रवि कुमार कुशवाहा, मंत्री उज्जवल जायसवाल, कार्य समिति सदस्य अर्श शर्मा एश्मीत सागर, गौरव अग्रहरि मनोनीत किए गए।

इस अवसर संरक्षक राजेश केसरवानी ने मनोनीत हुए सभी पदाधिकारी को बधाई देते हुए कहा कि फाउंडेशन कला एवं कलाकारों के हित के लिए कार्य करेगी। बधाई देने वालों में शत्रुघ्न जायसवाल, किशन चंद्र जायसवाल, अजय अग्रहरि कमलेश केसरवानी, नीरज केसरवानी, श्रेष्ठ चौरसिया, दीपक केसरवानी, आदि फाउंडेशन के कार्यकर्ता रहे।

व्यापारियों में साहस भरने व्यापारियों के बीच पहुंचे मंत्री

योगी सरकार में व्यापारियों को डराने, धमकाने और उत्पीड़ करने वालों की खैर नहीं - नन्दी

फूलपुर में सर्राफा कारोबारी के परिवार एवं अन्य व्यापारियों से की मुलाकात

प्रयागराज। फूलपुर थाना क्षेत्र के जमीलाबाद मोहल्ला निवासी सर्राफा कारोबारी अंकित सोनी के पुत्र सनी सोनी पर बुधवार की देर शाम जेल से छूट कर आए बदमाश और उसके साथियों द्वारा जानलेवा हमला करते हुए की गई फायरिंग की घटना के बाद व्यापारियों में साहस भरते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने गुरूवार को मौके पर जाकर सर्राफा व्यापारी के परिवारजनों और क्षेत्र के अन्य व्यापारियों से मुलाकात की। घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी सात पुश्तें याद रखें। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।

फूलपुर के जमीलाबाद में पहुंचने पर मंत्री नन्दी ने सर्राफा कारोबारी अंकित सोनी के पुत्र सनी सोनी से मुलाकात की एवं कुशलक्षेम जाना, जिस पर बदमाशों द्वारा बुधवार की देर शाम जानलेवा हमला किया गया था। इस दौरान सर्राफा कारोबारी अंकित सोनी के साथ ही अन्य व्यापारियों द्वारा बदमाशों के मनमानी की जानकारी दी गई। जिस पर मंत्री नन्दी ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि योगी सरकार में कानून का राज है। किसी भी व्यापारी एवं उद्यमी को बदमाशों एवं माफियाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। खुल कर व्यापार करें।

मंत्री नन्दी ने एसडीएम को निर्देश दिया कि सर्राफा कारोबारी पर जानलेवा हमले के सभी आरोपियों के आवास की भी जांच कराई जाए। यदि उनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया है तो जांच कराकर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाए। साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ताकि बदमाशों की सक्रियता से व्यापारी भयभीत न हों, उनका भय समाप्त हो।

जमीलाबाद निवासी सर्राफा कारोबारी अंकित सोनी का 22 वर्षीय पुत्र सनी सोनी पिता के साथ सर्राफा की दुकान पर बैठता था। व्यापार करता था। बुधवार की शाम वह अपने घर के बाहर बैठ कर आग ताप रहा था। तभी दो बाइक से आए चार बदमाश सनी सोनी के घर के पास पहुंचे और उसे पीटना शुरू कर दिया। खुद की जान बचाते हुए वह अपने ताऊ के घर की तरफ भागा। बदमाशों ने उसका पीछा करते हुए दौड़ाया और फायरिंग शुरू कर दी। कई राउण्ड फायरिंग की गई। यह तो संयोग ही था कि एक भी गोली सनी को नहीं लगी। वहीं बदमाश फायरिंग के बाद मौके से भाग निकले।

फोनपे के 10 साल भारत को सशक्त बनाने के एक दशक का जश्न

प्रयागराज। फोनपे ने हाल ही में इनोवेशन और भरोसे का एक शानदार दशक पूरा किया। भारत के फिनटेक इकोसिस्टम में 10 साल का यह सफर सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उत्सव है। इस दशक में फोनपे ने न केवल वित्तीय पहुँच को बढ़ाया है, बल्कि भारत में लेन-देन और पैसों को मैनेज करने के तरीके को भी बदला है। साल 2025 में, फोनपे ने 600 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स का आँकड़ा पार करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ के रूप में इसकी भूमिका को और मज़बूत कर दिया।

इस सफ़र के बारे में बताते हुए, फोनपे के फाउंडर और सीईओ समीर निगम जी ने कहा कि- 'हमारे दस साल के सफ़र का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि, भले हम कितनी भी दूर आ गए हों, शिखर अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। हमें अभी नहीं पता कि यह कैसा होगा और यही बात इसे रोमांचक बनाती है।

पुलिस उपायुक्त यमुनानगर द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

महर्षि भारद्वाज की आराधना के बिना प्रयागराज का पुण्य नही, महर्षि भरद्वाज प्रयागराज के धरोहर-जिलाधिकारी

प्रयागराज। भारद्वाज जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी प्रयागराज ने कहा कि महर्षि भारद्वाज प्रयागराज की पहचान है प्रयागराज के सम्मान के लिए शासन प्रशासन कटिबंध है पर्यटन और अन्य दृष्टि से जो भी संभव होगा यहां के तीर्थ का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का वैभवशाली इतिहास रहा है उसी के अनुरूप इसका विकास किया जाएगा। साधु संतों और प्रबुद्ध जनों ने प्रयागराज को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने संगम से 5 कोश परिधि में सार्वजनिक रूप से मांस मदिरा पर पाबंदी के मामले को सकारात्मक रूप से लेने की भी बात कही।

महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत यमुना पुरी ने कहा कि महर्षि भारद्वाज की पूजा के बिना प्रयागराज का पुण्य नहीं। बैकुंठ धाम के महंत श्रीधराचार्य ने कहा कि महर्षि भारद्वाज महान गुरु थे जिनके 10000 शिष्य थे इसी क्षेत्र में उनका विश्वविद्यालय था पहले कुलपति कहलाए। इस वैष्णव क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से मानस मंदिर की बिक्री हम संतो को कष्ट देता है। सरकार हम संतों की वाणी पर विचार करें। प्रयागराज विद्वत परिषद के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने महर्षि भारद्वाज के बारे में विस्तार से बताया।भीषण ठंड में, प्रयागराज विद्वत् परिषद के तत्वावधान में महर्षि भारद्वाज जयंती प्रयागराज दिवस धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में साधु संत प्रबुद्ध जन प्रयागराज के प्रथम गुरु महर्षि भारद्वाज को पुष्पांजलि करने जुटे।

माघ मास की पंचमी को प्रयागराज के प्रथम ज्ञात महान गुरु महर्षि भारद्वाज जिन्होंने हवा में उड़ने वाले यंत्र का आविष्कार किया था । माघ मेले के प्रवर्तक थे। आयुर्वेद के जनक हैं कि जयंती पर सुबह सवेरे माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया गया। महर्षि भारद्वाज जी के जन्मोत्सव के दिन ही प्रयागराज दिवस मनाया जाता है। जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी, सहित प्रबुद्ध जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। पुलिस बैंड व लोक कलाकारों ने शोभायात्रा में समा बांधा। जगह-जगह भरद्वाज जी की आरती व पुष्प वर्षा की गयी।

महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा की शोभायात्रा संगम पहुंची जहां गंगा पूजन किया गया। महर्षि भारद्वाज ही माघ मेला और कुंभ मेला के प्रवर्तक भी हैं। समारोह में महन्त श्रीधरानन्द, महन्त यमुनापुरी सचिव महानिर्वाणी अखाड़ा, जगदगुरू श्रीधराचार्य वैकुण्ठ धाम, नित्यनाथाचार्य जी, चन्द्र देव जी सच्चा आश्रम, राधामाधव दास, जगदगुरू नारायणा शांडिल्य गुरू संयोजक वीरेन्द्र पाठक, प्रो देवदत्त सरोदे प्रो आर एस पाण्डेय, अभिषेक मिश्र, आशुतोष शुक्ल ब्रजेन्द्र मिश्र, शशिकांत मिश्र, विक्रम मालवीय धीरज द्विवेदी, शैलेंद्र अवस्थी, डा प्रमोद शुक्ला, राहुल दुबे, डा श्रवण कुमार मिश्र संदीप शर्माअनिल मिश्र जगत नारायण तिवारी, योगमाता, सुनीता मिश्रा दीपू शुक्ला अशोक तिवारी, राजेश जायसवाल, अन्नू घिल्डियाल सभासद रत्नेश मिश्र कुलदीप सिंह रघुनाथ द्विवेदी डा रंजन बाजपेई, नीरज दीक्षित शार्दुल श्रीवास्तव आदि पुष्पांजलि में शामिल रहे।

पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी सहजता सरलता विनम्रता के त्रिवेणी थे

प्रयागराज। पूर्व राज्यपाल पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके आवास डॉ लोहिया मार्ग प्रयागराज में किया गया इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर, प्रोफेसर गिरीश चंद्र पार्टी, पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल, महापौर गणेश केसरवानी, ने पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी सहजता सरलता और विनम्रता के त्रिवेणी थे और सहृदय कवि और विधि के मर्मज्ञ अधिवक्ता रहे और एक सफल राजनेता के रूप में छह बार विधायक एक बार कैबिनेट मंत्री तीन बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जनता की सेवा की और जनप्रिय नेता रहे और विधानसभा अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल , बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने संवैधानिक पदों की मर्यादा बनाई और अपने जीवन काल तक आजाद शत्रु के रूप में पहचान बनाई।

इस अवसर पूर्व उपमहापौर मुरारी लाल अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता , पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा रणजीत सिंह, भाजपा नेता राम जी केसरवानी शिवेंद्र

मिश्रा, पदुम जायसवाल, भाजपा प्रवक्ता राजेश केसरवानी, ने कहा कि पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही थे और हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रेरक रहे उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम के संयोजक उनके सुपुत्र पूर्व महाधिवक्ता एवं भाजपा नेता नीरज त्रिपाठी एवं पुत्रवधू भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री श्रीमती कविता यादव त्रिपाठी रही। श्रद्धांजलि देने वालों में ज्ञानेश्वर शुक्ला, नवरत्न कत्याल, वन्दना सिंह, शिखा रस्तोगी, चंद्रा अहलूवालिया मुकेश कसेरा, शत्रुघ्न जायसवाल, शुभम मालवीय, एवं सैकड़ो अधिवक्ता गण पार्षद गण एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी।

विकास से कोसों दूर भिवंडी, लेकिन मनपा चुनाव में 40 उम्मीदवार करोड़पति

90 सीटों के लिए 439 उम्मीदवार मैदान में, सबसे अमीर नगरसेवक की संपत्ति 60 करोड़ से अधिक

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। मनपा की कुल 90 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें 439 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। एक ओर जहां भिवंडी को 'पावरलूम नगरी' और 'श्रमिकों की नगरी' के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर शहर आज भी बुनियादी विकास से कोसों दूर नजर आता है।

ठाणे और मुंबई जैसे विकसित शहरों के निकट होने के बावजूद भिवंडी में सड़क, जलापूर्ति, जलनिकासी, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद चुनाव मैदान में उतरे और निर्विरोध चुने गए जनप्रतिनिधियों की संपत्ति पर नजर डालें तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। उपलब्ध शपथपत्रों के अनुसार कुल 40 उम्मीदवार करोड़पति हैं।

सबसे अमीर उम्मीदवारों की सूची में प्रभाग क्रमांक 17 (ब) से बीजेपी के निर्विरोध चुने गए सुमित पाटील सबसे आगे हैं। उनकी कुल संपत्ति 60.97 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। प्रभाग क्रमांक 1 (ड) से कोणार्क विकास आघाड़ी के पूर्व महापौर विलास पाटील की संपत्ति 56.83 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं उनकी पत्नी, प्रभाग क्रमांक 1 (ब) से पूर्व महापौर प्रतिभा पाटील की संपत्ति भी 56.83 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। उनके पुत्र, प्रभाग क्रमांक 1 (क) से उम्मीदवार मयूरेश पाटील की संपत्ति 3.09 करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रभाग क्रमांक 23 (क) से बीजेपी के नारायण चौधरी की संपत्ति 55.75 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि प्रभाग क्रमांक 23 (ब) से बीजेपी की निर्विरोध चुनी गई भारती चौधरी की संपत्ति 35.57 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। प्रभाग क्रमांक 9 (अ) से शिंदेसेना के संजय म्हात्रे की संपत्ति 29.04 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रभाग क्रमांक 22 (अ) से बीजेपी की गीता नाईक की संपत्ति 26.13 करोड़ रुपये, प्रभाग क्रमांक 21 (ब) से शिंदेसेना की वंदना काटेकर की संपत्ति 25.23 करोड़ रुपये और प्रभाग क्रमांक 21 (ड) से शिंदेसेना के पूर्व उपमहापौर मनोज काटेकर की संपत्ति 24.71 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रभाग क्रमांक 6 (ड) से भिवंडी विकास आघाड़ी के जावेद दलवी की संपत्ति 23.99 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इसके अलावा प्रभाग क्रमांक 21 (ब) से जय हिंद सेना की उम्मीदवार दक्षता चौधरी की संपत्ति 20.99 करोड़ और प्रभाग क्रमांक 23 (ड) से बीजेपी के निलेश चौधरी की संपत्ति 20.99 करोड़ रुपये बताई गई है। प्रभाग क्रमांक 22 (क) से बीजेपी के श्याम अग्रवाल की संपत्ति 17.17 करोड़ रुपये, प्रभाग क्रमांक 20 (क) से कांग्रेस की वैशाली म्हात्रे की संपत्ति 15.43 करोड़ रुपये और प्रभाग क्रमांक 23 (ड) से निर्दलीय उम्मीदवार अशोक पाटील की संपत्ति 13.83 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रभाग क्रमांक 20 (ब) से कांग्रेस के विकास पाटील की संपत्ति 12.37 करोड़ रुपये, प्रभाग क्रमांक 20 (ड) से एनसीपी (एपी) के राहुल पाटील की संपत्ति 10.40 करोड़ रुपये, प्रभाग क्रमांक 1 (अ) से कोणार्क विकास आघाड़ी की नेहा काठवले की संपत्ति 7.85 करोड़ रुपये और प्रभाग क्रमांक 20 (ब) से बीजेपी के प्रकाश टावरे की संपत्ति 7.71 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं प्रभाग क्रमांक 22 (ब) से शिंदेसेना के कमलाकर पाटील की संपत्ति 7.51 करोड़ रुपये, प्रभाग क्रमांक 1 (अ) से बीजेपी की पद्मा गाजेंगी की संपत्ति 5.69 करोड़ रुपये, प्रभाग क्रमांक 20 (ड) से बीजेपी के यशवंत टावरे की संपत्ति 5.25 करोड़ रुपये, प्रभाग क्रमांक 6 (ब) से बीजेपी की दक्षाबेन पटेल की संपत्ति 5.11 करोड़ रुपये और प्रभाग क्रमांक 21 (अ) से उद्धवसेना के अशोक भोसले की संपत्ति 5.04 करोड़ रुपये से अधिक है।प्रभाग क्रमांक 1 (क) में बीजेपी विधायक महेश चौघुले के पुत्र मित चौघुले की संपत्ति 1 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि उद्धवसेना के भूषण रोकडे की संपत्ति 90.44 लाख रुपये है। एक ओर शहर की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों की संपत्ति वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में भिवंडी के मतदाताओं के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि आने वाले चुनाव में वे विकास को प्राथमिकता देंगे या फिर परंपरागत राजनीति को देंगे।

सपा उम्मीदवार एस.के भगत ने शुरू किया डोर टू डोर प्रचार, शुक्रवार को होगी विशाल जनसभा....

प्रभाग 11 में सपा पैनल को मिल रहा जनसमर्थन, संयुक्त रैली शाम 4 बजे किदवई नगर से निकलेगी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर प्रभाग क्रमांक 11 'अ' से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश कृष्णा भगत (एस.के.) ने अपने पैनल उम्मीदवारों के साथ डोर टू डोर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। चुनावी प्रचार के दौरान सपा पैनल को स्थानीय नागरिकों का उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है। सपा उम्मीदवार सुरेश कृष्णा भगत (एस.के.) अपने पैनल के उम्मीदवार अंसारी शमीम बानों मोहम्मद आसिफ (ब), शेख अरशिया निखत शफीक हुसैन (शफीक बाबू) (क) और हसीब शेर खान (ड) के साथ पूरे प्रभाग में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। प्रचार के दौरान नागरिकों से सीधे संवाद कर उन्हें सपा की नीतियों और विकास के वादों से अवगत कराया जा रहा है।

प्रभाग 11 में चुनावी मुकाबला रोचक होता जा रहा है। जहां एक ओर सपा पैनल मैदान में है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ((शरद चंद्र) और कांग्रेस के उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल कर जोरदार प्रचार और रैलियां निकाल रहे हैं। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (एकतावादी) और लोक हिंद पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी रण में डटे हुए हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का बढ़ता जनाधार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर सपा के प्रति लोगों का झुकाव दिखाई दे रहा है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है।

सपा उम्मीदवार सुरेश कृष्णा भगत (एस.के.) और उनके पैनल उम्मीदवारों की संयुक्त रैली और विशाल जनसभा का आयोजन शुक्रवार शाम 4 बजे किया जाएगा। यह रैली किदवई नगर स्थित प्रभाग (ड) के उम्मीदवार हसीब शेर खान के चुनावी कार्यालय से निकाली जाएगी और विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। एक मुलाकात के दौरान सुरेश भगत (एस.के.) ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रैली के माध्यम से जनता को एकजुट कर सपा पैनल को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने प्रभाग के नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में रैली और जनसभा में शामिल होकर समाजवादी पार्टी के पैनल को समर्थन दें। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे प्रभाग 11 में चुनावी माहौल और अधिक गर्माता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं।

नारपोली के डायग्नोस्टिक सेंटर में चोरी, शटर तोड़कर लाखों का सामान ले उड़े चोर...

लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और नकदी समेत 5.29 लाख की चोरी, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी.

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। नारपोली पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने देर रात सेंटर का शटर तोड़कर भीतर प्रवेश किया और लैपटॉप, मोबाइल फोन, टीवी तथा नकदी समेत लाखों रुपये का सामान चुरा ले गए। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता डॉ.अभिषेक सुकनराज जैन (32) नारपोली क्षेत्र में स्थित शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन करते हैं। 4 जनवरी की रात और 5 जनवरी की सुबह के बीच अज्ञात व्यक्ति ने सेंटर का शटर तोड़कर अंदर घुसपैठ की। इसके बाद चोर ने सेंटर में रखा एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, टीवी और नकद राशि समेत कुल लगभग 5.29 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया।

घटना की जानकारी 4 जनवरी को रात करीब 1 बजे सामने आई, जिसके बाद डॉ. जैन ने नारपोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच हो सकती है। वारदात के समय आरोपी ने हल्के रंग की फुल बाजू की शर्ट, काले रंग की पैंट और सिर पर टोपी पहन रखी थी। आरोपी की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। नारपोली पुलिस ने सेंटर और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान बरामद किया जाएगा। इस घटना के बाद नारपोली क्षेत्र के व्यापारियों और चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जिसकी आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक नवले कर रहे है।

'हर समस्या का होगा समाधान', मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दर्शन, एक-एक कर सुनी 150 लोगों की फरियाद

जमीन हड़पने वालों को जेल भेजने के निर्देश

गोरखपुर **(एजेंसी)**। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को गोरखनाथ मंदिर में 'जनता दर्शन' के दौरान विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने इस दौरान कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। उन्होंने कहा कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री योगी ने 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के दौरान करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं।

प्रभाग 1 में चुनावी सभा के दौरान भाजपा और कोणार्क विकास आघाड़ी समर्थक भिड़े, 20 पर केस

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी महानगरपालिका चुनाव के तहत प्रभाग क्रमांक 1 में आयोजित चुनावी सभा के दौरान भाजपा और कोणार्क विकास आघाड़ी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह घटना शिवाजी चौक के पास उस समय हुई, जब कोणार्क विकास आघाड़ी की चुनावी सभा और प्रचार कार्य चल रहा था। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया।पुलिस के अनुसार, गणपति मंदिर कोंबडपाडा परिसर में कोणार्क विकास आघाड़ी पैनल के प्रत्याशी विलास पाटिल, प्रतिभा पाटिल, नेहा काठवले और मयुरेश पाटिल की चुनावी सभा आयोजित की गई थी। इसी दौरान भाजपा समर्थकों सहित करीब 10 से 12 लोगों ने नारेबाजी और प्रचार को लेकर विरोध जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए।

आरोप है कि झड़प के दौरान लाठी-डंडों और हाथों से मारपीट की गई। इस दौरान कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा और सभा स्थल पर अफरातफरी मच गई। घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही निजामपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर भाजपा और कोणार्क विकास आघाड़ी के समर्थकों सहित कुल 20 लोगों के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, मारपीट और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।घटना के बाद शिवाजी चौक और आसपास के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि आगे कोई अप्रिय घटना न हो।

भिवंडी में नाबालिगों से जुड़े तीन अलग-अलग मामले, दो गुमशुदगी और एक पॉक्सो प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी शहर और आसपास के क्षेत्रों में नाबालिगों से संबंधित तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। इनमें दो मामलों में नाबालिगों के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई है, जबकि एक मामले में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तीनों मामलों में पुलिस ने कानून के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहला मामला कोंनगाव पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरवली गांव का है। यहां 14 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के लापता होने की शिकायत परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घरेलू कारणों से नाराज होकर किशोरी बिना बताए घर से निकल गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की घटना तो नहीं हुई।

दूसरा मामला निजामपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है। यहां 16 वर्षीय एक नाबालिग किशोर भिवंडी के खाड़ीपार इलाके में स्थित एक मदरसे से लापता हो गया है। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मदरसे सहित आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किशोर की सुरक्षित बरामदगी के लिए प्रयास जारी हैं।

तीसरा मामला भिवंडी शहर पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां 16 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप में 20 वर्षीय युवक विशालकुमार रामपोसुर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

एमडी ड्रग्स के साथ युवक गिरफ्तार, 1.20 लाख का मादक पदार्थ जब्त

साईनगर इलाके से 6 ग्राम मेफेड्रॉन बरामद

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शांतिनगर पुलिस स्टेशन की टीम ने एमडी (मेफेड्रॉन) ड्रग्स की तस्करी में लिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 1 लाख 20 हजार रुपये कीमत का 6 ग्राम मेफेड्रॉन (एमडी) जब्त किया है।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शांतिनगर पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस हवलदार निलेश ईश्वर महाले (43) की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8(क) और 21(ब) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 8 जनवरी की मध्य रात्रि के दरमियान साईनगर इलाक निशा अपार्टमेंट के पास की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हसन आमीर खान उर्फ हसन बंगाली (30) के रूप में हुई है। वह वर्तमान में नारपोली, भिवंडी के अजमेर नगर इलाके में रह रहा था, जबकि उसका मूल निवास पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में बताया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने मित्र शाहरूख उर्फ मंकी की मदद से 6 ग्राम मेफेड्रॉन को बेचने के इरादे से अपने पास रखे हुए था। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से एमडी ड्रग्स जब्त की और बाद में उसे विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को तय समय सीमा के भीतर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश गायकर कर रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस ड्रग्स तस्करी के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा मादक पदार्थ की आपूर्ति कहां से की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्रदेश में बेटियों को बड़ा तोहफा! दो बहनें पढ़ेंगी तो एक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त

योगी सरकार की तैयारी से लाखों परिवारों को बड़ी राहत

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई और अहम पहल की तैयारी कर रही है। सरकार का प्लान है कि अगर किसी परिवार की दो सगी बेटियां एक ही स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस मुफ्त कर दी जाए। इस योजना के तहत निजी और सरकारी, दोनों तरह के शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग को इस योजना की पूरी प्रक्रिया और शर्तें तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

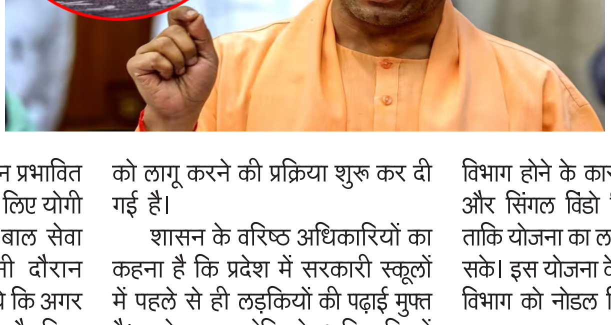

कोविड महामारी के दौरान प्रभावित परिवारों के बच्चों की मदद के लिए योगी सरकार ने पहले मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की थी। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए थे कि अगर किसी स्कूल, कॉलेज या निजी शैक्षणिक संस्था में दो सगी बहनें पढ़ रही हों, तो संस्थान से अपील की जाए कि वह एक बच्ची की ट्यूशन फीस माफ करे। अगर कोई निजी स्कूल या कॉलेज ऐसा करने से मना करता है, तो सरकार खुद उस छात्रा की फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। उस समय इस योजना के लिए सर्वे भी शुरू हुआ था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इस पर रोक लग गई थी। अब एक बार फिर इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पहले से ही लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए अलग योजनाएं, शिक्षा का अधिकार और स्कॉलरशिप व फीस प्रतिपूर्ति जैसी कई योजनाएं पहले से चल रही हैं। इन योजनाओं के जरिए अधिकतर छात्राएं कवर हो जाती हैं, लेकिन जो लड़कियां किसी कारण से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं, खासकर निजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली जरूरतमंद छात्राएं, उन्हें इस नई योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

पिछले महीने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लागू करने की रणनीति पर चर्चा की थी। बैठक में तय किया गया कि अलग-अलग शिक्षा विभाग होने के कारण एक नोडल विभाग और सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, ताकि योजना का लाभ सही तरीके से मिल सके। इस योजना के लिए महिला कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाए जाने का प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजा गया है। नोडल विभाग आय सीमा, पात्रता, शर्तें, बजट और लाभार्थियों की पहचान को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बाद योजना को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।

कानपुर गैंगरेप मामला : हटाए गए डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी, आरोपी पत्रकार गिरफ्तार

कानपुर **(एजेंसी)**। जिले के सचेंडी इलाके में 14 साल की लड़की के अपहरण और उससे सामूहिक बलात्कार के मामले में एक स्थानीय यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। मामले का आरोपी एक दारोगा अब भी फरार है। इस मामले को लेकर बड़े स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई की गयी है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कथित लापरवाही और तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के आरोप में पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) दिनेश चंद्र त्रिपाठी को पद से हटा दिया है और सचेंडी के थानाध्यक्ष विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सचेंडी क्षेत्र में 14 साल की एक लड़की को सोमवार रात करीब 10 बजे एक कार में जबरन बैठाकर अगवा किया गया था और उसके बाद उसे एक रेल पटरी के पास सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां करीब दो घंटे तक उससे सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसे बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर छोड़ दिया गया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने संवाददाताओं को बताया, ''पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर दारोगा अमित कुमार मौर्या और यूट्यूबर शिवबरन यादव को मुकदमे में नामजद किया गया है। यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि फरार दारोगा को पकड़ने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं।'

सीओ ने महिलाओं को दी गालियां एसएचओ ने पत्रकारों को मौके से भगाया

हरदोई **(एजेंसी)**। जिले के हरपालपुर क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। हरपालपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) सतेंद्र सिंह और सांडी थानाध्यक्ष राकेश यादव से जुड़े दो अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनसे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।

यह घटना हरपालपुर थाना क्षेत्र के खसौरा ग्राम पंचायत अंतर्गत दिउसीपुर गांव की है। यहां प्रशासन अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा था। सवायजपुर के एसडीएम मयंक कुंडू के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गांव पहुंची।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी आदेश शुक्ला ने प्रशासन से शिकायत की थी कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। शिकायत के बाद टीम ने जांच की और कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान जब टीम जमीन पर पहुंची, तो कुछ ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। विरोध करते हुए कई महिलाएं अपने-अपने घरों में जमीन पर बैठ गईं और उठने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कार्रवाई से पहले उन्हें पूरी सुनवाई और उचित प्रक्रिया का मौका नहीं मिला।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सीओ सतेंद्र सिंह महिलाओं को जबरन उठने के लिए कह रहे हैं।

एसए20 शानदार मंच पर आईपीएल से तुलना नहीं कर सकते : जेपी डुमिनी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जेपी डुमिनी ने एसए20 लीग को दक्षिण अफ्रीका और दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच करार दिया लेकिन साथ ही कहा कि इसकी तुलना इंडियन प्रीमियर लीग से नहीं की जा सकती। डुमिनी ने कहा कि एसए20 लीग की शुरुआत से स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को दुनिया भर के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के अधिक अवसर मिल रहे हैं जिससे देश के क्रिकेट को फायदा हो रहा है।

डुमिनी ने एसए20 द्वारा आयोजित ऑनलाइन मीडिया बातचीत के दौरान कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इसे आप आईपीएल के बराबर रख सकते हैं। मेरे लिए आईपीएल गोल्ड स्टैंडर्ड है। और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। मुझे लगता है कि आप आईपीएल से जरूर सीख सकते हैं। हमारे लिए एसए20 निश्चित रूप से एक दीर्घकालीन विजन है।' उन्होंने कहा, 'और इससे भी जरूरी बात यह है कि विश्व स्तरीय ढांचे के साथ दक्षिण अफ्रीकी प्रतिभा पर जोर दिया जा रहा है। आप उस प्रतिभा को कैसे ढूंढते हैं और एक और मंच कैसे देते हैं जिससे कि बेहद दबाव वाले और शीर्ष स्तरीय माहौल के बीच दक्षिण अफ्रीकी चयनकर्ताओं को खिलाड़ियों को चुनने का मौका मिले।'

डुमिनी ने कहा, 'जब 2008-2009 में आईपीएल शुरू हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। यह आपके प्रदर्शन और आपकी सोच को बेहतर बनाता है। और मुझे लगता है कि एसए20 के पास भी अब यही मौका है।' एसए20 लीग के प्रभाव का जिक्र करते हुए डुमिनी ने कहा, 'यह दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलना है, दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना है। आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। यह दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्रदर्शन करके चयन के मौके पाने का अवसर है। और मुझे लगता है कि यह एक और शानदार मंच देता है।'

सनराइजर्स ईस्टर्न केप में ट्रिस्टन स्टब्स को पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला है और डुमिनी ने उन्हें टीम को रास्ता दिखाने वाला नेतृत्वकर्ता बताया। उन्होंने कहा, 'वह (स्टब्स) कुछ समय से लगभग सभी प्रारूप में राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे हैं और अगर उन्हें मौका नहीं मिलता तो यह उनके लिए बहुत निराशाजनक होता।

सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी में लगाया सबसे तेज अर्धशतक

भारतीय स्टार को एक ओवर में ठोके 30 रन

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय क्रिकेट टीम में नजरअंदाज किए गए स्टार सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाकर इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया टीम में शामिल नहीं किए गए सरफराज सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर यह मुकाम हासिल किया। मुंबई के इस बल्लेबाज ने बड़ौदा के अतीत शेठ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2020-21 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 16 गेंदों में हाफ-सेंचुरी लगाई थी। सरफराज की इनिंग इसलिए भी खास थी क्योंकि उन्होंने भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा को एक ही ओवर में 30 रन मारे।

मुंबई के लिए खेल रहे सरफराज ने पंजाब के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और आखिरकार 20 गेंदों में 62 रन पर खत्म अपनी पारी समाप्त की जिसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे। हालांकि सरफराज की यह शानदार पारी बेकार चली गई क्योंकि मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड 7 का मैच पंजाब से सिर्फ एक रन से हार गई।

मुंबई ने 216 रनों का पीछा करते हुए अंगक्रिश रघुवंशी और मुशीर खान के विकेट क्रमशः 23 और 21 रन पर गंवा दिए। सरफराज ने अपनी 20 गेंदों में 62 रनों की तूफानी पारी से मुंबई को वापस पटरी पर लाया। हालांकि उन्हें मयंक मारकंडे ने आउट कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी 45 रनों की पारी से पारी को संभाला लेकिन उन्हें भी मारकंडे ने आउट कर दिया। बाद में सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और हार्दिक तमोरे क्रमशः 15, 12 और 15 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब के लिए, गुरनूर बरार और मयंक मारकंडे ने चार-चार विकेट लिए जबकि कृष भगत और हरनूर सिंह ने एक-एक विकेट लिया।

इससे पहले पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए। रमनदीप सिंह 74 गेंदों में 72 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अनमोलप्रीत सिंह ने 75 गेंदों में 57 रन बनाए। मुंबई के लिए मुशीर खान ने तीन विकेट लिए जबकि ओंकार तरमाले, शिवम दुबे और शशांक अटार्डे ने दो-दो विकेट लिए। इस जीत के साथ पंजाब ग्रुप सी में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहा। पंजाब और मुंबई दोनों ने क्वार्टर-फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।

बजट से पहले एसोचैम की सरकार से बड़ी मांग, हरित इस्पात उत्पादन को मिले प्रोत्साहन

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आगामी केंद्रीय बजट से पहले उद्योग निकाय एसोचैम ने सरकार से इस्पात क्षेत्र में हरित और टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाने की मांग की है। एसोचैम ने हाइड्रोजन आधारित 'डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन' (डीआरआई) तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने और इस बदलाव में इस्पात कंपनियों को रियायती दरों पर हरित वित्त उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है।

डीआरआई तकनीक में पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस की जगह गैस या हाइड्रोजन की मदद से कम तापमान पर लौह अयस्क को लोहे में बदला जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन काफी हद तक कम होता है। उद्योग निकाय का मानना है कि इससे स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

एसोचैम ने बजट पूर्व सुझावों में इस्पात संयंत्रों में वेस्ट-हीट रिकवरी सिस्टम को प्रोत्साहित करने और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित निजी बिजली संयंत्र स्थापित करने की भी वकालत की है। इससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होगी और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण संभव होगा।

इसके अलावा, उद्योग निकाय ने स्क्रैप संग्रह और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे आयात पर निर्भरता घटेगी। इसके लिए घरेलू रीसाइक्लिंग अवसंरचना को मजबूत करने और कौशल विकास की आवश्यकता बताई गई है।

एसोचैम ने यह भी कहा कि चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक होने के बावजूद भारत का इस्पात क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कच्चे माल की ऊंची लागत, रुपए में गिरावट और आयातित कोकिंग कोयले पर निर्भरता बड़ी समस्याएं हैं। उद्योग निकाय का मानना है कि आगामी बजट 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत को इस्पात और मूल्यवर्धित उत्पादों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का अहम अवसर प्रदान करता है। इसके लिए लौह अयस्क शोधन, आयात शुल्क में राहत और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई है।

मलेशिया ओपन : सिंधू की दमदार वापसी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश

कुआलालंपुर **(एजेंसी)**। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधू ने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली जापान की तोमोका मियाजाकी को महज 33 मिनट में 21-8, 21-13 से शिकस्त दी। लंबे समय तक चोट के कारण कोर्ट से दूर रहने के बाद वापसी कर रहीं पूर्व विश्व चैंपियन सिंधू ने इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया। आठवीं वरीयता प्राप्त मियाजाकी के खिलाफ यह उनकी दूसरी जीत रही, जिससे दोनों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड अब 2-1 हो गया है।

पहले गेम में सिंधू ने 5-1 की बढ़त के बाद लगातार 13 अंक बटोरते हुए 18-4 की निर्णायक बढ़त बना ली और गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में मियाजाकी ने थोड़ी चुनौती पेश की, लेकिन सिंधू ने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए 17-11 की बढ़त बनाई और मैच अपने नाम कर लिया।

क्वार्टर फाइनल में सिंधू का सामना चीन की गाओ फांग जी और जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त अकाने यामागुची के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा।

वहीं, भारतीय पुरुष खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। लक्ष्य सेन को हांगकांग-चीन के ली चेउक यिउ के खिलाफ 53 मिनट चले मुकाबले में 22-20, 15-21 से हार झेलनी पड़ी। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी यू क्यूई को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 70 मिनट के संघर्षपूर्ण मैच में 18-21, 21-18, 12-21 से पराजित हो गए।

ट्रंप के टैरिफ कहर से निवेशकों के डूबे 7, 68, 426.45 करोड़ रुपए, बाजार में मचा हाहाकार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अमरीका भारत पर रूसी तेल खरीदने पर 500 फीसदी का टैरिफ लगा सकता है। वैसे अभी तक इस बिल को संसद से मंजूरी नहीं मिली है लेकिन माना जा रहा है कि इस बिल को अमरीकी संसद का समर्थन मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में भारत पर एक मोटा टैरिफ अमरीकी सरकार की ओर से लग सकता है। इस टैरिफ के कहर के डर की वजह से भारत के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया और सैंसेक्स में 780 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली। खास बात तो यह है कि इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार निवेशकों के 7, 68, 426.45 करोड़ रुपए डूब गए हैं।

2 जनवरी को जहां सेंसेक्स 85, 762 के स्तर पर था, वहीं आज 84, 180 के स्तर पर बंद हुआ यानि चार कारोबारी सत्रों में इंडेक्स 1, 582 अंक टूट चुका है। इस गिरावट के चलते बीएसई पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 9 लाख करोड़ रुपए घट गया है।

बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 2 जनवरी को एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 4, 81, 24, 779.35 करोड़ रुपए था। मौजूदा सत्र में यह घटकर करीब 4, 72, 25, 753.38 करोड़ रुपए रह गया यानी महज चार दिनों में निवेशकों की संपत्ति में लगभग 899, 025.97 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक दिन में निवेशकों के 768, 426.45 करोड़ रुपए डूब गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा गिरावट के पीछे ज्यादातर वजहें वैश्विक और भू-राजनीतिक हैं। सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे प्रस्ताव को समर्थन दिया है, जिसके तहत रूस से व्यापार जारी रखने वाले देशों पर 500 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस आशंका ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है।

बिटकॉइन रचेगा इतिहास! एक्सपर्ट्स का दावा-2.25 लाख डॉलर तक जा सकता है भाव

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। तेज उतार-चढ़ाव से भरे 2025 के बाद बिटकॉइन एक बार फिर 2026 में निवेशकों के बीच चर्चा का केंद्र बनने वाला है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मानना है कि बिटकॉइन नई ऊंचाइयों को छू सकता है लेकिन इसके साथ भारी वोलैटिलिटी का जोखिम भी बना रहेगा। मैक्रो इकॉनमिक हालात, रेगुलेशन और निवेशकों के सेंटीमेंट को लेकर अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 को लेकर एक्सपर्ट्स के अनुमान बेहद अलग-अलग हैं। कुछ विश्लेषकों को उम्मीद है कि बिटकॉइन करीब 17इ गिरकर 75, 000 डॉलर तक आ सकता है, जबकि बुलिश कैंप इसे 150इ की छलांग के साथ 2, 25, 000 डॉलर तक पहुंचता देख रहा है। यह अंतर दिखाता है कि बाजार में भरोसे और डर–दोनों बराबर मौजूद हैं।

अक्टूबर में बिटकॉइन 1, 26, 000 डॉलर के ऑल-टाइम हाई तक पहुंचा था। इसके बाद मुनाफावसूली और मैक्रो दबाव के चलते साल के अंत तक यह करीब 80, 000 डॉलर तक फिसल गया। फिलहाल बिटकॉइन अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 30इ नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले छह महीनों में इसमें करीब 16.4इ की गिरावट दर्ज की गई है।

2025 की शुरुआत में बिटकॉइन को अमेरिका में अपेक्षाकृत अनुकूल रेगुलेटरी माहौल का फायदा मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती कार्यकाल के दौरान संस्थागत निवेश बढ़ा और बैंकों जैसी पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं की एंट्री से कीमतों को सपोर्ट मिला। डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनियों की आक्रामक खरीद ने भी रैली को हवा दी लेकिन साल के अंत में तस्वीर बदल गई।

राष्ट्रीय कोच पर लगा नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप, एनआरएआई ने उठाया सख्त कदम

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने निशानेबाजी कोचिंग स्टाफ के एक प्रमुख सदस्य अंकुश भारद्वाज को निलंबित कर दिया है क्योंकि एक नाबालिग निशानेबाज ने उन पर पिछले महीने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एनआरएआई ने पुष्टि की है कि फरीदाबाद में भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मोहाली निवासी भारद्वाज पर पॉस्को अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) (धमकी देने से संबंधित) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनआरएआई के सचिव राजीव भाटिया ने पीटीआई को बताया, 'एनआरएआई ने उन्हें निलंबित कर दिया है और हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। उन्हें नैतिक आधार पर निलंबित किया गया है। अब उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना होगा। जांच पूरी होने तक वह किसी भी तरह की कोचिंग गतिविधि से नहीं जुड़े रहेंगे।'

भाटिया ने कहा कि एनआरएआई ने 2024 में पेरिस

ओलंपिक के बाद 37 सदस्यीय कोचिंग टीम में भारद्वाज को स्थान देने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा, 'एनआरएआई की सिफारिश पर ही भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने उन्हें कोच नियुक्त किया था। यह सूरजकुंड में हुई यौन उत्पीड़न की घटना है।' पीड़िता ने जो प्राथमिकी दर्ज की है, उसके अनुसार, पिछले महीने करणी सिंह रेंज में एक अभ्यास सत्र के बाद यह घटना घटी थी। पिछले साल अगस्त से भारद्वाज के साथ प्रशिक्षण ले रही इस युवा निशानेबाज ने बताया कि वह इस घटना से सदमे में है और उन्होंने बार-बार पूछे जाने पर एक जनवरी को अपनी मां को इसकी जानकारी दी।

अपनी प्राथमिकी में 17 वर्षीय खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि भारद्वाज उसे मोहाली, पटियाला, देहरादून और दिल्ली जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए बुलाते थे, लेकिन वह हमेशा उसी दिन घर लौट आती थी। पीड़िता ने कहा कि घटना वाले दिन वह राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए टैक्सी से अकेले ही करणी सिंह रेंज गई थी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जब वह घर जा रही थी, तो कोच ने उसे अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए रुकने को कहा।

इस युवा खिलाड़ी ने अपनी शिकायत में बताया कि कोच ने पहले उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में एक होटल की लॉबी में मिलने के लिए कहा। लेकिन वहां पहुंचने पर कोच ने कथित तौर पर उसे अपने कमरे में आने के लिए मजबूर किया और कहा कि उसके प्रदर्शन को लेकर अधिक गहन चर्चा करने की जरूरत है। पीड़ित खिलाड़ी ने बताया, 'कोच ने मुझे लिफ्ट वाले एरिया में आने को कहा। जब मैं लिफ्ट वाले एरिया में गई तो कोच ने मुझसे कहा कि उन्होंने यहां एक कमरा बुक किया है, इसलिए मेरे कमरे में आ जाओ।

अब होटल की जरूरत नहीं! अपने घर का खाली कमरा ओयो को देकर हर महीने कमाएं लाखों

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अगर आपके पास कोई खाली कमर्शियल बिल्डिंग है या आप अपने पुराने होटल को एक नई पहचान देना चाहते हैं तो ओयो (ओयो) के साथ पार्टनरशिप करना एक शानदार विकल्प हो सकता है। आज के समय में अकेले होटल चलाना और ग्राहकों को ढूंढना मुश्किल काम है लेकिन ओयो जैसा बड़ा नेटवर्क आपके बिजनेस को 'ऑटो-पायलट' मोड पर डाल सकता है।

ओयो के साथ जुड़ना केवल एक ब्रांड नाम पाना नहीं है बल्कि यह आपके बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने का एक तरीका है। आपको विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ओयो ऐप और वेबसाइट के जरिए आपकी प्रॉपर्टी करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचती है। ओयो का 'डायनामिक प्राइसिंग' सिस्टम मांग के अनुसार कमरों का किराया खुद तय करता है जिससे ज्यादा मुनाफा होता है। बुकिंग से लेकर गेस्ट की सुविधाओं तक ओयो का सिस्टम हर कदम पर सपोर्ट देता है।

सामंथा रुथ प्रभु की नई फिल्म 'मां इंटि बंगारम' का पोस्टर रिलीज, पति राज निदिमोरु संग पहली बार जुड़ीं प्रोफेशनली

सामंथा रुथ प्रभु प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नई ऊंचाइयों को छूने के बाद फिर से एक्शन में लौट आई हैं। 2025 की फिल्म 'शुभम' से प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू करने के बाद, उन्होंने 'द फैमिली मैन 2' और 'सिटाडेलः हनी बनी' जैसे शोज के क्रिएटर राज निदिमोरु से शादी कर ली। 7 जनवरी को, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'मां इंटि बंगारम' का फर्स्ट लुक जारी किया। यह फिल्म राज निदिमोरु ने बनाई है।

फिल्म में एक्टिंग करने के अलावा, सामंथा 'मां इंटि बंगारम' में प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभा रही हैं। फिल्म में गुलशन देवैया और दिगंत भी अहम भूमिकाओं में हैं, और यह 'ओह! बेबी' की पिछली सफलता के बाद डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी के साथ उनका रीयूनियन है। सामंथा के पति और फिल्ममेकर राज निदिमोरु फिल्म के पीछे क्रिएटिव फोर्स के तौर पर जुड़े हुए हैं। इस कपल ने हाल ही में कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की।

सामंथा ने प्रोजेक्ट के मकसद और इरादों के बारे में खुलकर बात की है। हाल ही में एक प्रेस बातचीत के दौरान, उन्होंने शेयर किया, 'हम ऐसी कहानियों के लिए एक जगह बना रहे हैं जो आपको छू जाएं, ऐसी कहानियां जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहें। 'मां इंटि बंगारम' उसी विश्वास से पैदा हुई है - यह प्यार, अपनेपन और उन रोज़मर्रा की वैल्यूज़ का जश्न मनाती है जो हमें एक साथ बांधे रखती हैं, ' सामंथा ने कहा।

एक्टिंग से प्रोडक्शन में अपने बदलाव के बारे में बताते हुए, सामंथा ने समझाया, 'एक्टर से प्रोड्यूसर बनने तक का मेरा सफर ग्रोथ का रहा है, जिसमें मैंने सीखा भी है और कुछ भूला भी है। यह ऐसी कहानियों को आकार देने पर केंद्रित रहा है जो फ्रेम से परे हों, जो दिल से बात करें।'

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु के डेटिंग की अफवाहें कुछ समय से चल रही थीं। इस कपल ने 1 दिसंबर, 2025 को सीधे अपनी शादी की तस्वीरें पोस्ट करके इन अफवाहों का जवाब देने का फैसला किया।

'इलेवन' के बलिदान पर मिली बॉबी ब्राउन का बड़ा बयान 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के चौंकाने वाले अंत पर टूटा फैंस का दिल

मिली बॉबी ब्राउन ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 के विवादित एंडिंग पर रिएक्ट किया, जिसने दर्शकों के बीच काफी रिएक्शन पैदा किया, जिसमें कई लोग शो के मुख्य किरदार इलेवन की किस्मत को लेकर बहुत इमोशनल हो गए। आखिरी एपिसोड में ग्रुप ने वेकना को हराने के बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, जिसमें कुछ किरदार कॉलेज चले गए। ब्राउन द्वारा निभाई गई इलेवन ने खुद को कुर्बान कर दिया, यह एक ऐसा पल था जिसने साथी किरदारों और फैंस दोनों को हैरान कर दिया।

टुडम से बात करते हुए, ब्राउन ने इलेवन के पीछे रुकने के फैसले को 'खूबसूरत और सुकून देने वाला' बताया, यह कहते हुए कि उन्हें लगा कि यह किरदार के लिए एक सही अंत था। उन्होंने आगे कहा, 'मुझे बस लगता है कि यह बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाए, और दुख और दर्द खत्म हो जाए, ' इस बात पर ज़ोर देते हुए कि इलेवन की कहानी एक ज़रूरी नतीजे पर पहुँची। सीरीज़ के क्रिएटर्स, डफर भाइयों ने बताया कि फिनाले को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि हर किरदार ने वेकना को हराने में एक सार्थक योगदान दिया। मैट डफर ने कहा, 'हर किरदार के पास एक खास हुनर है, और वे इसे इस आखिरी लड़ाई में ला पाते हैं।' टीम वर्क की भावना जानबूझकर डंगऑन एंड ड्रैगन्स कैंपेन की सहयोगी भावना की याद दिलाती थी।

उन्होंने विस्तार से बताया, 'हर कोई किसी न किसी सार्थक तरीके से योगदान देता है... इस मायने में, यह डंगऑन एंड ड्रैगन्स कैंपेन के क्लाइमेक्स जैसा भी लगता है, जहाँ हर किरदार के पास एक खास हुनर होता है, और वे इसे इस आखिरी लड़ाई में ला पाते हैं।'

वेकना को हराने में इलेवन के हिस्से के लिए उसे अपने अंदर की उन क्षमताओं को 'इस्तेमाल' करने की ज़रूरत थी, जिनका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ब्राउन ने इस पल पर अपना नज़रिया शेयर करते हुए कहा, 'यह मेरे लिए बहुत नया है क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक अंतिम बात है, ' जो किरदार और एक्ट्रेस दोनों के लिए सीन के अनोखे इमोशनल वज़न को दिखाता है।

राज ठाकरे ने भाजपा को बताया खतरा, नगर निकाय चुनाव में मराठी अस्मिता का मुद्दा कितना बड़ा?

मुंबई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि जो ताकतें मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहती हैं, वही आज केंद्र और राज्य की सत्ता में हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नगर निकायों पर भी ऐसी शक्तियों का नियंत्रण हो गया, तो मराठी मानूस पूरी तरह कमजोर हो जाएगा।

राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे का संयुक्त साक्षात्कार का पहला भाग गुरुवार को सामना में प्रकाशित हुआ। इसमें राज ठाकरे ने कहा कि वह और उनके चचेरे भाई किसी राजनीतिक अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में मराठी मानूस के अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ आए हैं।

जानें साक्षात्कार के दौरान ठाकरे भाइयों ने क्या-क्या कहा?

ठाकरे परिवार के चचेरे भाइयों का साक्षात्कार शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत और जाने-माने निर्देशक महेश मांजरेकर ने लिया। पिछले महीने, चचेरे भाइयों ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की थी। इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले लोग न केवल आजीविका के लिए आ रहे हैं, बल्कि वे अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हैं।

उन्होंने दावा किया, 'यह एक पुराना घाव है... मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के सपने को साकार करने के प्रयास जारी हैं।'

उन्होंने कहा कि आज का माहौल कुछ वैसा ही है जैसा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान था जब गुजरात मुंबई को अपना हिस्सा बनाना चाहता था। उन्होंने दावा किया, 'अगर भाजपा नगर निगमों पर नियंत्रण कर लेती है तो मराठी मानुष कुछ भी नहीं कर पाएंगे।'

नगर निकायों को नियंत्रित करना जरूरी

एमएनएस प्रमुख ने कहा कि अगर इस पर सीमाएं तय करनी हैं तो नगर निकायों को नियंत्रित करना जरूरी है, खासकर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, मीरा-भयंदर, कल्याण-डोम्बिवली और छत्रपति संभाजीनगर में।

राज्य सरकार को निशाना बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा विकास का प्रचार करती है, लेकिन इससे प्रगति के बजाय विनाश होता है। उन्होंने दावा किया कि यह 'बिना योजना के विकास' है।

भाजपा सरकार को खुद नहीं पता कि वे क्या चाहती है

पूर्व राज्य मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'सरकार को खुद नहीं पता कि वह क्या चाहती है।' उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, सत्ता में बैठे लोग मराठी या महाराष्ट्र से हैं, लेकिन उनका मुंबई की जनता से कोई लेना-देना नहीं है। वे केवल ठेकेदारों के लिए काम करते हैं।

मादप पदार्थों के खतरे को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना

राज ठाकरे ने बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में धन के इस्तेमाल और आसानी से उपलब्ध मादक पदार्थों के बीच संबंध स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि नशीली दवाओं के खिलाफ छापे बंद हो गए हैं और राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी पर कोई नियंत्रण नहीं है।

विशेष साक्षात्कार : विनया विष्णु सावंत

(पूर्व नगरसेवक । महायुति उम्मीदवार, वार्ड 39)

'वार्ड 39 में यह चुनाव वादों का नहीं, काम के रिकॉर्ड का है'

प्रश्न 1 : आप वार्ड 39 से महायुति उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। इसका क्या महत्व है?

उत्तर : महायुति सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व का संकल्प है। वार्ड 39 में महायुति की उम्मीदवार होना मेरे लिए जिम्मेदारी भी है और भरोसा भी। इसका मतलब है कि वार्ड के विकास के लिए मेरे पीछे मजबूत सरकार और निर्णायक नेतृत्व खड़ा है।

प्रश्न 2 : आप पहले भी वार्ड 39 की नगरसेवक रह चुकी हैं। इसे आप अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हैं?

उत्तर : बिल्कुल। मैं वार्ड 39 के लिए कोई नया नाम नहीं हूं। मैंने पहले नगरसेवक के रूप में काम किया है, समस्याओं को करीब से देखा है और समाधान भी दिए हैं। जनता ने मेरा काम देखा है, इसलिए इस बार मैं वादों की सूची नहीं, अपने काम का रिकॉर्ड लेकर जनता के सामने हूं।

प्रश्न 3 : विरोधी कह रहे हैं कि यह चुनाव केवल सत्ता का है, आप क्या कहेंगी?

उत्तर : यह चुनाव सत्ता का नहीं, सेवा और जवाबदेही का है। जिन लोगों को पहले मौका मिला, उन्होंने क्या किया – यह वार्ड की जनता जानती है। आज वार्ड 39 बदलाव नहीं, बेहतर और भरोसेमंद नेतृत्व चाहता है।

प्रश्न 4 : वार्ड 39 की प्रमुख समस्याएं आपकी नज़र में क्या हैं?

उत्तर : सड़कें, जल निकासी, नियमित सफाई, सुरक्षा और नागरिक सुविधाएं – ये आज भी सबसे बड़े मुद्दे हैं। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना मेरी प्राथमिकता होगी।

प्रश्न 5 : आपने चुनाव कार्यालय को 'समाधान केंद्र' कहा है, इसका आशय क्या है?

उत्तर : मेरे लिए चुनाव कार्यालय केवल प्रचार का माध्यम नहीं है। यह वार्ड 39 के नागरिकों की समस्याएं सुनने और तुरंत कार्रवाई करने का केंद्र बनेगा। नगरसेवक का काम सिर्फ जीतना नहीं, हर दिन जनता के बीच रहना होता है।

प्रश्न 6 : महायुति सरकार होने से वार्ड को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर : जब नगरसेवक और सरकार एक दिशा में काम करते हैं, तो विकास रुकता नहीं। महायुति के माध्यम से वार्ड 39 को तेज़ी से फंड, योजनाएं और प्रशासनिक सहयोग मिलेगा – यही असली विकास की गारंटी है।

प्रश्न 7 : आपकी जीत को लेकर आत्मविश्वास किस आधार पर है?

उत्तर : आत्मविश्वास का आधार मेरा काम है। भगवान राम हमारे साथ हैं और जनता का भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वार्ड 39 की जनता भावनाओं में नहीं, सच्चाई के साथ फैसला करेगी।

प्रश्न 8 : जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी?

उत्तर : सबसे पहले अधूरे विकास कार्यों को पूरा करना और प्रशासन को जवाबदेह बनाना। वार्ड 39 को सिर्फ योजनाओं की नहीं, जमीन पर दिखने वाले विकास की जरूरत है।

प्रश्न 9 : वार्ड 39 की जनता के लिए आपका अंतिम संदेश?

उत्तर : मैं आपसे नारे के लिए वोट नहीं मांग रही हूं। मैं आपसे काम, ईमानदारी और भरोसे के लिए समर्थन चाहती हूं। एक बार फिर मौका दीजिए, वार्ड 39 को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना मेरी जिम्मेदारी होगी।

पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद को लाने वाले महर्षि भरद्वाज - डॉ जी एस तोमर

भरद्वाज प्रतिमास्थल, भरद्वाज चौराहा पर भरद्वाज जयन्ती धूमधाम से मनाई गई

प्रयागराज विद्वत परिषद के द्वारा प्रयागराज के प्रथम और महान गुरू महर्षि भरद्वाज जी की जयन्ती संत महात्माओं, वटुकों एवं प्रयागराज के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में धूमधाम से मनाई गई । ज़िलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की । कार्यक्रम के संयोजक श्री बीरेन्द्र पाठक ने महर्षि के जीवन एवं योगदान पर विस्तृत प्रकाश डाला । इस अवसर पर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हण्डिया के पूर्व प्राचार्य एवं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो.(डॉ.) गिरीन्द्र सिंह तोमर ने आयुर्वेद को पृथ्वी लोक पर लाने वाले महर्षि भारद्वाज के विषय में विस्तार से चर्चा की । उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सृष्टि के प्रारंभ काल से ही पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित विधा रही है । ब्रह्मा ने सबसे पहले अनादि काल

से प्रचलित आयुर्वेद का स्मरण किया । उन्होंने यह शाश्वत ज्ञान प्रजापति को दिया । प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को एवं अश्विनी कुमारों ने इन्द्र को यह ज्ञान दिया । पृथ्वी लोक पर बढ़ते हुए रोगों को देखकर महर्षियों ने एक संभाषा कर चिंता व्यक्त की । इसके निवारण के लिए महर्षि भारद्वाज ने आगे आकर इन्द्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया एवं इन्द्र से प्राप्त आयुर्वेद के इस ज्ञान को प्राणिमात्र की सेवा के लिए प्रचारित एवं प्रसारित किया । अतः पृथ्वी लोक पर आयुर्वेदावतरण का श्रेय महर्षि भारद्वाज को जाता है ।इस अवसर पर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गंगा नाथ झा परिसर के आचार्य प्रो राम कृष्ण पाण्डेय, प्रो देवदत्त सरोदे सहित राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागी शताधिक पीएच.डी. स्कॉलर्स एवं रिसोर्स पर्सन डॉ अवनीश पाण्डेय भी उपस्थित रहे ।

चुनावी सरगर्मियों के बीच शिवसेना का 'राष्ट्रधर्म', भारतीय सेना को दिए 50 कंटेनर

मुंबई।राज्य में 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की ओर से सेना को 50 कंटेनर देने का निर्णय लिया. इनमें से 46 कंटेनर पहले ही सीमा पर भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष चार कंटेनर गुरुवार (8 जनवरी) को उरण से सेना के हवाले किए गए. युवा सेना के मराठवाड़ा निरीक्षक बाजीराव चव्हाण की उपस्थिति में ये कंटेनर भारतीय सेना के अधिकारी सूबेदार सयाजी निगडे और नायक सूबेदार आनंद गायकवाड़ को सौंपे गए.

शिवसेना की सिंदूर महारक्तदान यात्रा

10 अगस्त 2025 को शिवसेना की सिंदूर महारक्तदान यात्रा जम्मू-कश्मीर पहुंची थी. इस दौरान डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील सहित महाराष्ट्र के करीब एक हजार पहलवानों ने शिवसेना के माध्यम से भारतीय सेना के जवानों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया था.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस

महारक्तदान यात्रा में भाग लेते हुए स्वयं रक्तदान किया था. उसी समय भारतीय सेना के ब्रिगेडियर युद्धवीर सिंह ने सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए कंटेनर उपलब्ध कराने का अनुरोध उपमुख्यमंत्री शिंदे से किया था.

सेना के लिए उपमुख्यमंत्री ने भेजे कंटेनर

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा पर युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव आया है. इस दौरान और इसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं. ऐसे में सीमा पर तैनात जवानों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेने के लिए भूमिगत बंकरों की आवश्यकता होती है. लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थायी सीमेंट-कंक्रीट बंकर बनाना संभव नहीं होने के कारण सेना ने कंटेनरों की मांग की थी.

कंटेनरों के माध्यम से तेजी से बंकर तैयार किए जा सकते हैं और सैनिकों, हथियारों व अन्य सामग्री को सुरक्षित रखा जा सकता है. इसी संदर्भ में सेना के अधिकारियों ने पत्र लिखकर उपमुख्यमंत्री शिंदे से कंटेनर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था.

शिवसेना एकनाथ शिंदे ने लिया फैसला

इस अनुरोध का सम्मान करते हुए शिवसेना की ओर से भारतीय सेना को 50 कंटेनर देने का निर्णय लिया गया. इनमें से 46 कंटेनर पहले ही सीमा पर भेजे जा चुके हैं, जबकि अंतिम चार कंटेनर गुरुवार (8 जनवरी) को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए. युवा सेना के मराठवाड़ा निरीक्षक बाजीराव चव्हाण की पहल पर ये कंटेनर उपलब्ध कराए गए हैं.

भारतीय सेना ने इन कंटेनरों को अपने खर्च पर सीमावर्ती क्षेत्रों तक ले जाने की तैयारी जताई, जिसके चलते उरण से शेष चार कंटेनर सेना को सौंपे गए. समय पर की गई इस मदद के लिए भारतीय सेना ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना का आभार व्यक्त किया है. बाजीराव चव्हाण ने जानकारी दी कि जल्द ही सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपमुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात कर इस संबंध में आभार-पत्र सौंपेंगे.

नासिक में डिप्टी सीएम शिंदे का ऐलान, मुंबई और पुणे की तरह लागू होंगे समान नियम, क्या होगा फायदा?

नासिक । महाराष्ट्र के नासिक शहर को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सौगात दी है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार (8 जनवरी) को आश्वासन दिया कि शहर की पुरानी इमारतों के पुनर्विकास को गति देने के लिए मुंबई, पुणे और ठाणे की तरह नासिक में भी समान नियम लागू किए जाएंगे. उद्योग मंत्री उदय सामंत की पहल पर, नासिक क्रेडाई के उपाध्यक्ष उदय घुगे से फोन पर बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री शिंदे ने इन बदलावों के प्रति सहमति जताई.

नासिक महानगरपालिका चुनाव प्रचार के सिलसिले में गुरुवार (8 जनवरी) को उद्योग मंत्री उदय सामंत नासिक दौरे पर थे.

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने गणमान्य व्यक्तियों से किया संवाद

इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न उद्यमियों, संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों से संवाद किया. इसी समय, नासिक शहर की पुरानी इमारतों के पुनर्विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडाई की ओर से यह मांग की गई कि मुंबई, पुणे और ठाणे की तरह नासिक में भी समान विकास नियम लागू किए जाएं.

इस पर उदय सामंत ने तुरंत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर संपर्क किया और क्रेडाई के उपाध्यक्ष उदय घुगे की उनसे बातचीत करवाई. नासिक के डेवलपर्स की समस्याओं को समझते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद नासिक में भी समान नियम लागू किए जाएंगे.

मुंबई, पुणे और ठाणे में नए विकास नियंत्रण नियमों के अनुसार, 9 मीटर

चौड़ी सड़क से सटी इमारतों को 1.8 से 2 एफएसआई तथा उस पर अतिरिक्त 0.5 इंसेंटिव एफएसआई मिलता है, जिससे कुल एफएसआई 2.5 तक हो जाती है. इसके कारण सड़क से सटी इमारतों का पुनर्विकास डेवलपर्स के लिए व्यावहारिक बनता है.

नासिक को मिलती है इतनी एफएसआई

नासिक में फिलहाल केवल 1.4 एफएसआई मिलती है और अतिरिक्त 0.3 प्रतिशत एफएसआई खरीदनी पड़ती है. इसी वजह से 9 मीटर सड़क से सटी इमारतों का पुनर्विकास अटका हुआ है, यह बात क्रेडाई के उपाध्यक्ष उदय घुगे ने उपमुख्यमंत्री शिंदे के ध्यान में लाई.

मुंबई, पुणे और ठाणे में इमारत की ऊंचाई की गणना करते समय पोडियम पार्किंग को शामिल नहीं किया जाता, जबकि नासिक में पोडियम पार्किंग सहित ऊंचाई मापी जाती है, जिससे डेवलपर्स को नुकसान होता है. यह मुद्दा भी क्रेडाई की ओर से उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया.

उपमुख्यमंत्री ने दिए नियम लागू करने के आदेश

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद मुंबई, पुणे और ठाणे की तरह नासिक शहर में भी समान नियम लागू किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में नगर विकास विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे.

नासिक शहर में 9 मीटर चौड़ी सड़कों से सटी इमारतों की संख्या करीब 8 से 10 हजार के बीच है. यदि मुंबई, पुणे और ठाणे की तर्ज पर नासिक में भी समान नियम लागू होते हैं, तो इन इमारतों के पुनर्विकास को बड़ा लाभ मिलेगा.

अपनी बात उपमुख्यमंत्री शिंदे तक पहुंचाने और इस पर तुरंत ठोस कदम उठाने के लिए नासिक क्रेडाई के अध्यक्ष गौरव ठक्कर और उपाध्यक्ष उदय घुगे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया है.

नितेश राणे का विपक्ष पर हमला, कहा- जिहादियों का काम कर रहे विपक्षी, लगाए गंभीर आरोप

मुंबई। मुंबई में आगामी 2026 के नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नितेश राणे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर का विकास केवल करदाताओं और मुंबई के निवासियों के लिए होगा, न कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के लिए।

राणे बोले भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं

राणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि जो लोग देश को बुरी नजर से देखते हैं, उन्हें यहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा हमारी पार्टी की विचारधारा और सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर भरोसा जताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जनता जानती है कि शहरों के विकास के लिए महायुति और भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में जीत उसी की होगी जो 'आई लव महादेव' की विचारधारा रखता हो, और इसी सोच वाला व्यक्ति महापौर की कुर्सी पर बैठेगा।

भाजपा नेता विपक्ष पर साधा निशाना

मनसे और शिवसेना (यूबीटी) के गठबंधन पर तंज कसते हुए राणे ने कहा, क्या वे मराठी वोट को मजबूत करना चाहते हैं या हिंदू वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं? उन्होंने पूछा, 'क्या मराठी हिंदू नहीं हैं?' राणे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने हिंदुओं को बांटने के लिए सुपारी ले रखी है और वे जिहादियों का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष का असली मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई 'बुर्काधारी' महिला महापौर बने।

बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, मेट्रो-बस किराए में छूट समेत कई वादे

मुंबई। पुणे महानगरपालिका के होने वाले चुनाव से महज कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संपत्ति कर माफ करने, महिलाओं को मेट्रो रेल और नगरीय बस सेवा के किराए में छूट सहित विभिन्न रियायतें देने का वादा किया गया है. बीजेपी ने अपना 'संकल्प पत्र' बुधवार को पार्टी के पुणे से लोकसभा सदस्य मुरलीधर मोहोल, राज्य के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और माधुरी मिसल, विधायकों और अन्य नेताओं की उपस्थिति में नगर निकाय के चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया।

केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ दल ने इसमें वादा किया है कि अगर वह पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) में जीत दर्ज करती है, तो वह 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देगी और शहर की बसों और मेट्रो रेल में महिलाओं को किराए में रियायत भी देगी. पार्टी ने राज्य सरकार की 'लाडकी बहिन योजना' के तहत गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये देने और 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले घरों और फ्लैटों के लिए संपत्ति कर माफ करने का भी वादा किया है। मोहोल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमने पिछले घोषणापत्र में किए गए अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है. हमने पुणेवासियों को मेट्रो ट्रेन सेवा, पानी का समान वितरण और नदी तट विकास का आश्वासन दिया था और हमने इन वादों को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार, बालेवाडी और बानेर जैसे शहर के कुछ हिस्सों में स्मार्ट सिटी पहल के तहत परियोजनाएं बनाई गई हैं।

सांसद मुरलीधर मोहोल ने कहा, हमने 30 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक पुणेवासी को वार्षिक मुफ्त चिकित्सा जांच का आश्वासन भी दिया है. हम जल्द ही यहां एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अस्पताल का निर्माण करेंगे और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पास एक डेटा सेंटर भी बनाया जाएगा. महाराष्ट्र में पुणे और 28 अन्य महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और नतीजे अगले दिन घोषित किए जाएंगे।

पुणे महानगरपालिका में कुल 165 सीटें हैं. बीजेपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना 123 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 138 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. तीनों दल राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ 'महायुति' के घटक हैं. वहीं, विपक्षी 'महा विकास आघाडी'में शामिल कांग्रेस, शरद पवार की राकांपा (एसपी) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) क्रमशः 99, 43 और 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)